नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचारपत्र • वर्ष 5 अंक 12
जनवरी 2004 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

मजदूर वर्ग के हरावलों से नये साल का आह्वान

मजदूर आंदोलन के क्रान्तिकारीकरण की कोशिशें तेज करो!

सम्पादक

'बिगुल' का यह अंक आपके हाथ में पहुंचने तक इक्कीसवीं सदी का एक और नया साल अपना सफर शुरू कर चुका होगा। देश की लुटेरी जमातें नये साल के जश्न की खुमारी उतार रही होंगी। हमारे ये देशी साहब भला नये साल का जश्न क्यों न मनायें! अंग्रेज साहबों के देश छोड़कर भागने के बाद आजादी तो इन्हीं को मिली है। 'आजाद' हिन्दुस्तान में जिनका 'स्वर्ग' धरती पर उतर आया है वे स्वर्ग-सुख क्यों न लूटें! लेकिन हम मेहनतकशों के लिए नया साल क्या मायने रखता है? हमारे लिए इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि हम लुटेरों के इस 'स्वर्ग पर धावा' बोलने की अपनी तैयारियां और तेज करने का संकल्प लें। नहीं तो नये साल की शुरुआत हमारे लिये कैलेण्डर की तारीख बदल जाने से ज्यादा अहमियत नहीं रखती।

हमारा संकल्प खोखला न साबित हो, इसकी बुनियादी शर्त यह है कि हम उस जमीन की ठीक-ठीक पहचान करें जहां हम खड़े हैं। केवल तभी हम सामने मौजूद चुनौतियों-कठिनाइयों का सही ढंग से मुकाबला करने की रणनीति-कार्यनीति और ठोस अमली कार्यक्रम तय कर सकते हैं।

आज देश का मजदूर वर्ग और उसका आंदोलन कहां खड़ा है? अगर हम गुजरे एक दशक पर नजर दौड़ाएं तो यह बेरहम सच्चाई हमें नजर आ जायेगी कि देश के शासक वर्गों और साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग कोई कारगर प्रतिरोध नहीं खड़ा कर सका। निजीकरण, छंटनी-तालाबंदी और विदेशी पूंजी की लूट को बेलगाम करने वाली भूमंडलीकरण नीतियों का सवाल हो या अफगानिस्तान और इराक पर खुले साम्राज्यवादी हमले का—मजदूर वर्ग का इनके खिलाफ कोई कारगर दखल नहीं रहा। क्या यह कड़वी सच्चाई चीख-चीख कर हमें आगाह नहीं कर रही कि मजदूर वर्ग के हरावल इस दुखदायी स्थिति के कारणों की गहराई में जाकर पड़ताल करें। आखिर हम कब तक देश और दुनिया में उठ खड़े होने वाले छिटपुट जनप्रतिरोधों के आइने में भविष्य के विश्वव्यापी जनसंघर्षों के उभार का अक्स देखकर एक झूठे भ्रम की मृगमरीचिका में भटकते रहेंगे। झूठी उम्मीदों में जीते रहने से हमेशा ही बेहतर होता है कि कड़वे यथार्थ को नंगी आंखों से देखने का साहस जुटाया जाये। किसी को ये बातें निराशाजनक लग सकती हैं लेकिन हमारा मानना है कि खोखले आशावाद में जीने से अधिक नुकसानदेह बात कुछ नहीं हो सकती। जब तक किसी आंदोलन में वर्तमान के स्याह पहलुओं को नंगी आंखों से देखने का साहस नहीं पैदा हो जाता तब तक भविष्य के उजाले तक बढ़ने की राहें नहीं ढूंढी जा सकतीं।

मेहनतकशों के लिए नये साल का एक ही अर्थ हो सकता है कि हम लुटेरों के 'स्वर्ग पर धावा' बोलने की अपनी तैयारियां और तेज करने का संकल्प लें। हमारा संकल्प खोखला न साबित हो, इसकी शर्त है कि हम कड़वी सच्चाई को खुली आंखों से देखने का साहस करें और सामने मौजूद चुनौतियों-कठिनाइयों का सही ढंग से मुकाबला करने की रणनीति-कार्यनीति और ठोस कार्यक्रम तय करें

यह बात अपनी जगह सौ फीसदी सही है कि विश्व पूंजीवादी तंत्र अधिकाधिक गहरे संकटों में धंसता चला जा रहा है। भूमंडलीकरण की नीतियां दुनिया के पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लुटेरों को थोड़ा बहुत फौरी राहत भले दे दें वे इसे अमर नहीं बना सकतीं। दुनिया भर में इन नीतियों से पैदा होने वाली तबाही को मेहनतकश अवाम चुपचाप यूं ही बर्दाश्त करता नहीं रह सकता। वह कर भी नहीं रहा है। जगह-जगह जन असंतोष अपने आप अलग-अलग रूपों में फूट भी रहा है। हमारे देश का मजदूर वर्ग भी एकदम चुप नहीं बैठा रहा है। जगह-जगह उसने जुझारू लड़ाइयां भी लड़ी हैं। लेकिन क्या क्रांतिकारी बदलाव के बारे में आशावादी होने के लिए बस इतना ही काफी है? कत्तई नहीं! पूंजीवादी-साम्राज्यवादी निजाम के खिलाफ बड़े से बड़ा स्वतःस्फूर्त जनउभार भी क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में नहीं बढ़ सकता अगर मेहनतकश अवाम की क्रांतिकारी पार्टी इसकी अगुवाई न करे और इसे संगठित कर क्रांतिकारी दिशा न दे। लेकिन क्या हमारे देश में सर्वहारा के हिरावल भावी जनउभार, जो कि अवश्यंभावी है, की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं? भले ही यह अफसोसनाक बात हो, बेहद आशावादी होने पर भी इस सवाल का जवाब हां में देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है।

आज के हालात इस बात के साफ संकेत

(पेज 8 पर जारी)

पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्षों को गुमराह करने वाला महातमाशा

विशेष संवाददाता

दिल्ली। आगामी 14-21 जनवरी के बीच मुंबई में साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के विरोध के नाम पर एक महातमाशा होने जा रहा है, जिसके बारे में देश और दुनिया के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के एक हिस्से में अनेक तरह के भ्रम मौजूद हैं। विश्व सामाजिक मंच यानी डब्ल्यू.एस.एफ. (वर्ल्ड सोशल फोरम) की ओर से आयोजित हो रहे इस आयोजन की तैयारियों के लिए राजधानी दिल्ली और अन्य कई स्थानों पर मीटिंगों-गोष्ठियों का सिलसिला चालू है।

इस मंच ने अपने घोषणापत्र में 'एक दूसरी दुनिया संभव है' जैसा लुभावना नारा उछाला है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि यह मंच साम्राज्यवादी-पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के खिलाफ एक नयी विश्व व्यवस्था की पैरोकारी करने वाला मंच है। लेकिन इस मंच के उद्देश्यों, उसके गठन की प्रक्रिया, इसमें भागीदार प्रमुख संगठनों के चरित्र और इसे आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थाओं के चरित्र की छानबीन की जाये तो किसी को भी यह समझते देर नहीं लगेगी कि इस मंच की असली मंशा कुछ और ही है। यह दुनिया भर में साम्राज्यवाद-पूंजीवाद विरोधी जनसंघर्षों को गुमराह करने के लिए खड़ी की गयी एक धोखे की टट्टी है। इसलिए मेहनतकशों के हरावलों की यह अहम जिम्मेदारी बनती है कि वे हर मुमकिन तरीके से इसकी असलियत को आम लोगों के बीच बेनकाब करें, जिससे धुंधलका छंट सके और साम्राज्यवाद- पूंजीवाद विरोधी जनसंघर्षों की सही दिशा उभरकर सामने आ सके।

विश्व सामाजिक मंच (डब्ल्यू.एस.एफ.) का मुंबई आयोजन

विश्व सामाजिक मंच धोखे की टट्टी है!
जनसंघर्षों को गुमराह करने की साजिश है!
पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को सुधारा नहीं जा सकता, उसे केवल तबाह किया जा सकता है!
'दूसरी दुनिया' केवल समाजवादी व्यवस्था ही हो सकती है।

डब्ल्यू.एस.एफ. कैसे बना?

सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, जिसमें विश्व सामाजिक मंच अस्तित्व में आया। वर्ष 1999 में विश्व व्यापार संगठन की सिएटल बैठक के दौरान हुए जबर्दस्त जनप्रदर्शन के बाद साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण की नीतियों के विरोध में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे हुए जनसंघर्ष लगातार उठते रहे हैं। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले और इराक पर ताजा हमले और कब्जे से दुनिया भर में साम्राज्यवादी लुटेरों के खिलाफ जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता गया है। खुद अमेरिका और यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के भीतर भी युद्ध विरोधी प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गयी थी। इससे सभी साम्राज्यवादी डाकुओं की चिंतित हो जाना लाजिमी है। साम्राज्यवादियों के विचारक यह बखूबी जानते हैं कि जनअसंतोष को अगर उन्होंने सिर्फ खुले दमन के हथकंडों से दबाने की कोशिश की तो ये और भड़क उठेंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकालने के बारे में सोचा, जिससे विरोध का छद्म भी बना रहे और पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट-तंत्र को कोई नुकसान भी न पहुंचे। इसी पृष्ठभूमि में और साम्राज्यवादियों की कपटी चालों से विश्व

(पेज 10 पर जारी)

आपस की बात

उत्तरांचल प्रदेश की जम्बो मंत्री परिषद पर्वतीय क्षेत्र के विकास का या विनाश का नक्शा

कहावत है कि खरबूजे का रंग देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उ.प्र. की रंग बदल की राजनीति का असर उत्तरांचल प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर पड़ने की आशंका चुनावी राजनीति के धुरन्धर बुजुर्ग नारायण दत्त तिवारी को लगी है। पर्वत विकास पुत्र के नाम से नवाजे गये इस कांग्रेस के सिपहसालार का अपने गृह राज्य के कांग्रेसी विधायक दल पर से विश्वास भंग होता स्पष्ट नजर आ रहा है।

सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस राज्य विधान-मंडल के सदस्यों की पसन्द से नहीं बल्कि विधान मण्डल में आपसी फूट के कारण हाई कमान की पसन्द से राज्य की बागडोर संभाली थी।

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि अपनी लाश पर उत्तरांचल प्रदेश की गठन की बात करने वाले तिवारी जी (जो उत्तरांचल अलग राज्य के गठन आंदोलन के पक्ष में नहीं रहे) कांग्रेस के तथाकथित नेताओं को धकियाते हुए राज्य गठन होते ही प्रथम निर्वाचित राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं।

अगर मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक जीवन का विश्लेषण किया जाये तो यह निस्संदेह कहा जायेगा कि पंडित जी जितने वाकपटु हैं उतने गांधी परिवार के प्रति वफादार भी हैं। यही कारण है कि नारायण दत्त के राजनीतिक सफर में गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी समय-समय पर मील का पत्थर साबित होती रहती हैं। उ. प्र. के प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने में तिवारी जी को अगर संजय गांधी भक्ति का पुरस्कार मिला तो उत्तरांचल प्रदेश की निर्वाचित सरकार का सदर बनने में सोनिया स्नेह का बहुत बड़ा हाथ होने की बात कही जाती है।

जो भी हो, तिवारी जी को सांपनाथ के साथ नागनाथ से भी डर लग रहा है। जहां विपक्षी भाजपा की जोड़-तोड़ की राजनीति का डर है वही अपने विधायकों की टूटन का डर भी सता रहा है। उ.प्र. में दल-बदल का मौसम चल रहा था : कहीं वहां की यह बयार उत्तरांचल में आ गई तो मुख्यमंत्री जी की बहुमत वाली सरकार को धराशायी होते देर नहीं लगेगी।

विकास के नाम पर कुर्बानी देने वाली उत्तरांचल की जनता अपने राज्य में विकास की बात खोजने में पलके बिछाये राह देख रही है। मगर शासक वर्ग देहरादून की गद्दी की लड़ाई में व्यस्त हैं।

सन् 1974 में तत्कालीन उ.प्र. के मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए पृथक पर्वतीय विकास का बजट शासन में रखा। इसके उपरान्त पर्वतीय विकास की दर में कुछ परिवर्तन हुआ मगर यह भी ऊंट के मुंह में जीरा ही चरितार्थ हुआ।

विकास की भूख ने जनता को आन्दोलन पर मजबूर कर दिया। पृथक राज्य की मांग के साथ जनता ने विकास का मुद्दा उठाकर कुर्बानियां दीं। मुजफ्फरनगर काण्ड, खटीमा काण्ड आदि घटनाओं तथा कुर्बानियों से शासक वर्ग हिल गये। फलस्वरूप उत्तरांचल का जन्म हुआ।

अपनी कंगाल अर्थव्यवस्था के साथ जन्म लिए इस शिशु राज्य में कांग्रेस विधान मंडल के 40 सदस्यों में से 36 सदस्य आज मंत्री पद से सुशोभित हैं।

कांग्रेस के ही नरसिंह राव को केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिमण्डल गठन करने का सौभाग्य है। उ. प्र. में तो यह रिकार्ड बनता-बिगड़ता रहता है। मगर उत्तरांचल में कांग्रेस की एक दलीय सरकार है। 70 सदस्य वाली विधान सभा में एक मनोनीत सदस्य है। कुल सदस्यों की 50 प्रतिशत की रेखा पार कर चुकी मंत्री परिषद क्या राज्य के बजट पर प्रभाव नहीं डालेगी?

उत्तरांचल में जहां, गरीबी, बेरोजगारी मुंह बाये खड़ी है वहां यह मंत्री परिषद की लम्बी फौज विकास में आड़े नहीं आयेगी? या सिर्फ राज्य शासन का वजूद बचाने की कवायद है।

वर्तमान सरकार का यह विकास का नहीं विनाश का नक्शा झलक रहा है।

–विजय कुमार सिंह
खटीमा, ऊधमसिंह नगर

जागृति गान

उठो-उठो मजदूर किसानो
अपनी ताकत को पहचानो।

लाभ-बद्ध हो आगे जाना
हर शोषण से मुक्ति दिलाना
श्रमिकों का नव राज्य बनाना
उठो-उठो मजदूर किसानों
श्रम-जीवी ताकत पहचानो।

नया सूर्य धरती पर लाना
अंधकार को मार भगाना
हर जीवन सुख-पूर्ण बनाना
उठो-उठो मजदूर किसानों
शत्रु-मित्र को खुद पहचानो।

क्रांति राग हम सबको गाना
त्याग-शौर्य के दीप जलाना
नया मनुज हमको बन जाना
उठो-जगो मजदूर किसानो
इंकलाब करने की ठानो।

– डा. त्रिवेणी प्रकाश त्रिपाठी
कोलकाता

मेरी कहानी

'बिगुल' के नवंबर, 03 अंक में छपी खबर "हादसा कंपनी में, मुआवजा ई.एस.आई. के मत्थे" में जिस मजदूर का जिक्र है, वह मैं ही हूं। आपने मेरे बारे में छापा, इससे नोएडा के मजदूरों की क्या हालत है, सबको पता ही चल गया होगा। लेकिन उस खबर में आपने मालिक का नाम नहीं दिया है। ए.जी. इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लि. के मालिक मल्कीत सिंह और अनिल पाठक हैं। इनकी नोएडा में सेक्टर-4 में ए-100 और सेक्टर-6 में जी-37 दो कंपनियां हैं। इनमें हैंगर और पावर प्रेस हैं, जहां लोहा गलाकर गाड़ी का पार्ट बनता है।

–रवि सिंह, नोएडा

बिगुल के पाठक साथियों और शुभचिन्तकों से एक अपील

'बिगुल' के पिछले सात वर्षों का सफर तरह-तरह की कठिनाइयों-चुनौतियों से जूझते गुजरा है। इस दौरान अनेक नये हमसफर हमारी टीम से जुड़े हैं और पाठक-साथियों का दायरा भी काफी बढ़ा है। कहने की जरूरत नहीं कि अब तक का कठिन सफर हम अपने हमसफरों और शुभचिन्तकों के संग-साथ के दम पर ही पूरा कर सके हैं। हालात संकेत दे रहे हैं कि आगे का सफर और अधिक कठिन और चुनौती भरा ही नहीं बल्कि जोखिमभरा भी होगा। हमें विश्वास है कि हम अपने दृढ़संकल्प और हमसफर दोस्तों की एकजुटता के दम पर आगे ही बढ़ते रहेंगे।

'बिगुल' अपने पुरअसर तेवर और अपने विशिष्ट जुझारू अंदाज के साथ आपके पास नियमित पहुंचता रहे, इसके लिए अखबार के आर्थिक पहलू को और अधिक पुख्ता बनाना जरूरी है। जाहिर है कि यह अपने संगी-साथियों और शुभचिन्तकों की मदद के बिना मुमकिन नहीं। हमारी आपसे पुरजोर अपील है कि :

- बिगुल के स्थायी कोष के लिए अधिकतम संभव आर्थिक सहयोग भेजें।
- जिन साथियों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है वे यथाशीघ्र नवीनीकरण करा लें।
- बिगुल के नये सदस्य बनायें।
- बिगुल के वितरण को और व्यापक बनाने में सहयोग करें।
- कुछ वितरक साथियों के पास बिगुल के कई अंकों की राशि बकाया है। इसे यथाशीघ्र भेजकर बिगुल नियमित प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

सहयोग राशि बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से सम्पादकीय कार्यालय के पते पर भेजें। बैंक ड्राफ्ट 'बिगुल' के नाम से भेजें।

—सम्पादक

'बिगुल' का स्वरूप, उद्देश्य और जिम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनवादों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

राहुल फाउण्डेशन का नया प्रकाशन

बोल्शेविक पार्टी का इतिहास

जे.वी. स्तालिन द्वारा लिखित और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की केन्द्रीय समिति के एक आयोग द्वारा सम्पादित यह पुस्तक सोवियत संघ में 1938 में छपी थी। यह पुस्तक दुनियाभर के कम्युनिस्टों के लिए एक अनिवार्य पाठ्यपुस्तक रही है, और आगे भी रहेगी। यह पुस्तक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग द्वारा समाजवाद के लिए सफल संघर्ष और समाजवादी निर्माण के अनुभवों और सबकों का निचोड़ प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक हमें सामाजिक विकास के नियमों के ज्ञान से लैस करती है तथा पूँजी और श्रम के बीच जारी विश्व ऐतिहासिक महासमर में समाजवाद की अपरिहार्य विजय में विश्वास पैदा करती है। निम्न-पूंजीवादी पार्टियों-गुटों, सभी प्रकार के अवसरवादियों, आत्मसमर्पणवादियों, जनता के दुश्मनों और पार्टी के भीतर वामपंथी दुस्साहसवाद तथा दक्षिणपंथी अवसरवाद की प्रवृत्तियों के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष चलाते हुए तपकर निखरी बोल्शेविक पार्टी का यह इतिहास हर देश के क्रान्तिकारियों के लिए एक प्रकाशस्तम्भ है।

पृ. 360 मूल्य : 80 रुपये

प्रतियों के लिए जनचेतना के केन्द्रों से संपर्क करें

(पते के लिए देखें नीचे)

नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक बिगुल

सम्पादकीय कार्यालय : 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006

सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मयांदपुर, मऊ

दिल्ली सम्पर्क : 29, यू.एन.आई. अपार्टमेण्ट, जीएच-2, सेक्टर-11, वसुंधरा-गाजियाबाद-201010

ईमेल : bigulakhbar@hotmail.com

मूल्य: एक प्रति–रु. 3/- वार्षिक–रु. 40.00 (डाक खर्च सहित)

बिगुल

'जनचेतना' की सभी शाखाओं पर उपलब्ध :

1. डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
2. जनचेतना स्टाल, काफी हाउस बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ (शाम 5 से 8 बजे तक)
3. जाफरा बाजार, गोरखपुर-273001
4. 989, पुराना कटरा, यूनिवर्सिटी रोड, मनमोहन पार्क, इलाहाबाद
5. जनचेतना सचल स्टाल (ठेला) चौड़ा मोड़, नोएडा (शाम 5 से 8)

मेहनतकश साथियों के लिए जरूरी कुछ पुस्तकें

कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढांचा –लेनिन 5/-
मकड़ा और मक्खी –विल्हेल्म लीब्कनेख्त 3/-
ट्रेड यूनियन काम के जनवादी तरीके –सजी रोस्तोवस्की 3/-
अनवज्वर है सर्वहारा संघर्षों की अग्निशिखाएं 10/-
समाजवाद की समस्याएं, पूंजीवादी पुनर्स्थापना और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति 12/-
क्यों माओवाद? 10/-
बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने के बारे में 5/-
मई दिवस का इतिहास 5/-
अक्टूबर क्रान्ति की मशाल 12/-
पेरिस कम्यून की अमर कहानी 10/-

बिगुल विक्रेता साथी से मांगें या इस पते पर 17 रु. रजिस्ट्री शुल्क जोड़कर मनीआर्डर भेजें जनचेतना, डी-68, निराला नगर, लखनऊ।

पंतनगर में संयुक्त मोर्चा गठित, मजदूर आंदोलन की राह पर संघर्ष को सही दिशा में आगे ले जाना होगा

बिगुल संवाददाता

पन्तनगर। लम्बी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तीन प्रमुख यूनियनें—पंतनगर कर्मचारी संगठन, श्रमिक कल्याण संघ व सफाई मजदूर कांग्रेस—एक मंच पर एकत्रित हो गयी हैं। इलाके के मजदूर कर्मचारी यूनियनों-संगठनों-मंचों के साझा मंच 'संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा' के प्रयास से पंतनगर में गठित ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने वि.वि. प्रशासन को 14 सूत्री मांग पत्रक देकर संघर्ष का ऐलान कर दिया है।

मोर्चे की ओर से कुलपति को सम्बोधित मांग पत्रक में विश्वविद्यालय फार्म के मजदूरों को वि. वि. कर्मचारी के अनुरूप वेतन, वेतन भुगतान व अन्य लाभ देने; 340 दिन पूरा कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण, ठेका प्रथा खत्म करके सीधी भर्ती करने, स्वच्छकों को लेबर कांट्रेक्ट धारा 70 के अनुसार ठेका प्रथा से मुक्त करने व मास्टर लिस्टेड मृतक आश्रितों को नियोजित करने; विश्वविद्यालय फार्म या अन्य भूमि के हस्तान्तरण से पूर्व वहां कार्यरत श्रमिकों व उनके उत्तराधिकारियों के उचित पुनर्वास हेतु आवासीय भूमि उपलब्ध कराने सहित वेतन-भत्ते-आवास सम्बन्धित 14 मांग शामिल हैं।

मांग पत्रक में शामिल ज्यादातर मांगें मजदूरों की पुरानी मांगें हैं। फार्म के मजदूरों को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अनुरूप सुविधाएं व राजकीय कोषागार से वेतन के भुगतान पर तो पहले समझौता भी हो चुका है, लेकिन फिर भी शासन की स्वीकृति के बहाने यह मुद्दा लटका हुआ है। लेकिन इस मांग पत्रक में सबसे अहम मुद्दों में है—लम्बे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा का खात्मा व फार्म की जमीनों का उद्योगों के लिए हस्तांतरण।

विश्वविद्यालय में 8-9 वर्षों से कार्यरत ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने 240 दिन नियमित कार्य की सीमा को काफी पहले पूरा कर लिया है, जिनको नियमित करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश भी है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसे लटकाये हुये है। यही हाल मास्टर लिस्टेड आश्रित मजदूरों का है। वर्तमान में ये सभी लगभग पौने दो सौ मजदूर ठेकेदारी के मातहत काम कर रहे हैं।

अलग-अलग यूनियनों के बंटवारे व किसी सकारात्मक आंदोलन के अभाव में विश्वविद्यालय प्रशासन ने किस्तों में ठेका प्रथा लागू करते हुए पिछले । मई से यहां पूर्णतः ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया है और दिल्ली की एक कम्पनी को ठेका मिलने के बाद लगभग 1100 मजदूर यहां एक झटके में ठेकेदार के मातहत आ गये। इस मुद्दे को देर से ही सही लेकिन इस वक्त मोर्चे की घटक यूनियनों ने अपना मुद्दा बनाया है। हालांकि यह मांग पत्रक का नौवां मुद्दा है।

इसी प्रकार, एक समय में 16000 एकड़ में बने इस विश्वविद्यालय की कुछ जमीनें एन.जी.ओ. को दी जा चुकी है, कुछ पहले ही जिला मुख्यालय बनने में चली गई और अब 3300 एकड़ जमीन में नयी औद्योगिक बस्ती बनाकर देशी व बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। इस मसले पर मोर्चे ने उस भूमि पर कार्यरत मजदूरों को आवासीय भूमि देने की बात उठायी है।

बहरहाल मोर्चा बनने से जहां एक तरफ मजदूरों में उत्साह व खुशी दोनों है, वहीं वि.वि. प्रशासन बेहद परेशान है। शुरू में तो उसने मोर्चे से बात करने की जगह अलग-अलग यूनियनों से बात करने का प्रयास किया। कुलपति ने तो बाकायदा बयान जारी किया कि वह पंजीकृत यूनियनों को ही जानता है, अपंजीकृत मोर्चे को नहीं। उसने परोक्ष रूप से मोर्चे को तोड़ने का भी प्रयास किया। कुछ अन्य यूनियनें तो मोर्चे की शुरुआती बैठकों में भी शामिल होने के बावजूद मोर्चे में शामिल नहीं हुईं। प्रशासन की तो सदैव ही यह नीति रही है कि 'बांटो और राज करो।'

उधर मोर्चे ने अपने मांगपत्रक के साथ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक के अदालती आदेश के बावजूद न केवल यहां सभायें हो रही हैं, बल्कि सांकेतिक जुलूस निकालकर मजदूरों ने न्यायालय के स्टे को तोड़ भी दिया है। मोर्चा आंदोलन को क्रमशः ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है।

पंतनगर के मजदूरों को इस मोर्चे से काफी उम्मीदें हैं। जनरल डायर की देशी औलादों द्वारा मजदूरों के बर्बर हत्याकाण्ड के पच्चीस वर्ष बाद एक बार फिर सन 1978 के आंदोलन की याद आने लगी है। स्थितियां एक बार फिर बेहद कठिन हैं। एक तो यह उदारीकरण-निजीकरण-ठेकाकरण का दौर है। दूसरे शासक वर्ग पहले से ज्यादा दमनकारी हो चुका है। तीसरे ढेरों यूनियनों का बंटवारा है और नेतृत्व में अवसरवाद, मठाधीशी व अर्थवाद का भटकाव है। ऐसे नेतृत्व द्वारा मजदूर बार-बार ठगे जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में मोर्चे की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। हालात का तकाजा है कि यहां की शेष यूनियनों को भी मजदूर हित में एक मंच पर आना ही चाहिए। इसके साथ ही, आंदोलन के नेतृत्वकारी निकाय को भी, बेहद संजीदगी व ईमानदारी के साथ संघर्ष की रणनीति बनानी चाहिए और बुनियादी मुद्दों को हल करने तक अपना संघर्ष चलाना चाहिए।

बार-बार ठगे व छले गये यहां के मजदूरों को यह आशंका है कि कहीं मोर्चा बीच में ही न टूट जाये या किसी खास मुकाम पर अचानक संघर्ष रोक न दिया जाये। इसलिए नेतृत्व की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही हालत पर चौकस नजर रखने की जिम्मेदारी मजदूरों की भी बनती है।

पहाड़-मैदान का झगड़ा छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो!

उत्तरांचल राज्य गठन के तीन वर्ष— अन्तिम किस्त

बिगुल टीम

उत्तरांचल राज्य गठन के तीन वर्ष के दौरान वही सब कुछ हुआ जो राज्य गठन से पूर्व हो रहा था, अथवा उदारीकरण के इस दौर में जो कुछ पूरे देश में हो रहा है। यानी बदस्तूर जारी जायज-नाजायज लूट, रोजगार में कटौती, निजीकरण का जोर, पूंजीपतियों की बढ़ती आक्रामकता, दमन का कसता शिकंजा, भ्रष्टाचार के नये-नये कारनामे, कोर्ट-कचहरी, शासन-प्रशासन का खुलकर पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा होना और जनता की तबाही-बर्बादी।

इन तीन वर्षों में देश की दो प्रमुख पार्टियों के तीन मुख्यमंत्रियों की सरकारें काबिज रहीं। पहले भाजपाई सरकार रही, जिसके आला कमान दिल्ली में काबिज हैं और छह वर्षों से देशी पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों की चाकरी बजा रहे हैं। औने-पौने दामों में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने, नौकरी के रास्ते बन्द करते जाने, मजदूर विरोधी कानून बनाने, पोटा का पाटा चलाने में, मीठी-चुपड़ी बातों में झूठ परोसने में महारत हासिल कर चुकी केन्द्र की भाजपा सरकार की ही राह पर राज्य की भाजपा सरकार को भी चलना ही था।

राज्य की बागडोर आज उसी कांग्रेस पार्टी के हाथों में है जिसने न केवल आजादी के 56 वर्षों के दौरान देश में पूंजीपतियों को पनपने, मजबूत होने की नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम किया, सामन्ती भूस्वामियों को पूंजीवादी भूस्वामी बनने में, बड़े फार्मरों-कुलकों को विकसित होने की जमीन तैयार की, आम मजदूरों-किसानों की तबाही के रास्ते पर ले गयी, दमन के नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये वरन उदारीकरण की नयी आर्थिक नीतियों के जनक भी यही हैं। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी तो देश में घोषित आपातकाल (1975-77) के काले दिनों के कुशल दमनकारी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

ऐसे में, राज्य गठन के बाद वही होना था, जो हो रहा है। राज्य से उद्योगों के पलायन/बन्दी का पहले से जारी क्रम और बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र का हिलट्रान पहले से ही बन्द हो चुका था, ऋषिकेश स्थित दवा कारखाना आईडीपीएल बन्दी की स्थिति में चल ही रहा था, इस दौरान पूर्णतः बन्द हो गया। एच एम टी के सिर पर बन्दी की तलवार लटक ही रही है। काशीपुर-जसपुर की कताई मिलें उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बन्द कताई मिलों की तरह बन्द पड़ी हैं। तमाम सरकारी घोषणाएं हो रही हैं और मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। यहां कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।

निजी क्षेत्र की एएसपी व मैग्नेसाइड व मिनरल्स लि. जैसे कारखाने सब्सिडियां और सहूलियतें हड़पने के बाद पहले ही पलायन कर चुके हैं, जबकि सलोरा, नैनी सेमीकण्डक्टर, उषा रेक्टीफायर, प्रकाश पिक्चर ट्यूब जैसे तमाम कारखाने इस दौर में पलायित हुए हैं। राज्य के सबसे मुनाफा वाले सेक्टर विद्युत विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया राज्य गठन से पूर्व शुरू हुई थी जो अब मुकम्मल शक्ल ले रही है। प्रदेश सरकार ने दो कदम और आगे बढ़ाते हुए पूंजीपतियों के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों को आधी से भी कम करते हुए 1.90 रुपये प्रति यूनिट कर दिया, जबकि उसने घरों में व कृषि में उपयोग होने वाली विद्युत दरों को बढ़ा दिया। यानी मुनाफाखोरों के लिए सस्ती दर पर और जनता के लिए महंगी बिजली।

राज्य बनने के बाद 22 विधायकों का स्थान 70 विधायकों ने ले लिया, जिनमें से लगभग 40 के पास लाल बत्ती की गाड़ियां मौजूद हैं। ताजा निर्णय में राज्य सरकार ने विधायक निधि में 25 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है। राज्य के मंत्रिमंडल का बंटवारा भी कुशलता से किया गया है। जैसे परिवहन मंत्री की कई बसें पहले से ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में चल रही हैं और श्रम मंत्री ही (दोनों मंत्री एक ही व्यक्ति हैं) कांग्रेसी ट्रेडयूनियन महासंघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

इन तीन वर्षों में भ्रष्टाचार नेताशाही-नौकरशाही का सदाचार बन गया है। नित नये घोटाले तीनों मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में चर्चा में आते रहे हैं। वर्तमान समय में दरोगा भर्ती घोटाला व पटवारी घोटाला सुर्खियों में है।

इस दौरान, यहां रोजगार के पहले से ही सीमित अवसर और भी कम होते गये हैं। इसकी शुरुआत तो राज्य गठन के वक्त ही हो गयी थी, जब पहली सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के आदेश से नवगठित सचिवालय में नियमित भर्ती की जगह सुरक्षा-सफाई-बागवानी आदि कामों को ठेके पर देने की घोषणा हुई। राज्य गठन के बाद भाजपा सरकार ने राज्य में नियमित भर्ती पर रोक का शासनादेश जारी कर दिया और राज्य के प्रमुख रोजगार—शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु, विजिटिंग प्रोफेसर आदि नामों से ठेका प्रणाली लागू की। बाद की कांग्रेस सरकार ने इसे और आगे बढ़ाते हुए तमाम विभागों में अनुबंध व अशकालिक भर्तियों पर रोक का शासनादेश जारी करते हुए अस्थायी कामों पर भी अस्थायी भर्ती के लिए भी सरकारी इजाजत को अनिवार्य बना दिया। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तो घोषित तौर पर ठेकेदारी प्रथा लागू हो गयी। विद्युत, सड़क निर्माण, परिवहन, वन, जल-संस्थान आदि स्थानों पर भी ठेका या अनुबंध प्रणाली लागू है।

सफाई के लिए तो और भी नये तरीके का सरकारी फरमान आया है। स्थानीय निकाय में पहले नियमित सफाई कर्मियों को रखने की जगह ठेकेदारी शुरू हुई, फिर अनुबंध के आधार पर इनसे काम लेने की शुरुआत हुई (हालांकि 90 दिन पूरा होने से पूर्व ही इन्हें 'ब्रेक' दे दिया जाता था)। अब नये शासनादेश के तहत मुहल्लों में कमेटियां बनेंगी और सफाईकर्मी वे रखेंगी, जिनके वेतन का एक हिस्सा नगरपालिका उठायेगी और एक हिस्सा कमेटी।

तीन वर्षों में तीनों सरकारों ने निरंकुश दमन के सिलसिले को जारी रखा। तीन वर्ष पूर्व रुद्रपुर के रवीन्द्रनगर की बंगाली आबादी का पुलिसिया दमन हो, छात्रों, शिक्षकों, मजदूरों के संघर्षों का दमन हो अथवा शिक्षा बन्धु के नियमितीकरण के लिए हुए प्रदर्शन पर राजधानी देहरादून में पुलिसिया दमन हो, सभी इसी कड़ी के हिस्सा हैं।

कुल मिलाकर, राज्य गठन के तीन वर्ष देशी-बहुराष्ट्रीय मुनाफाखोरों की बढ़ती लूट, भूमि और शराब माफियाओं की और बढ़ती जकड़बंदी, निजीकरण-छंटनी-तालाबंदी, भ्रष्टाचार, बढ़ते दमन और आम जनता के तबाही-बर्बादी के ही तीन वर्ष रहे हैं। नवगठित इस छोटे राज्य की गाड़ी भी सरपट उसी राह पर दौड़ रही है। और दौड़नी भी थी) जिस राह पर भूमण्डलीकरण व उदारीकरण के इस दौर में पूरे देश की गाड़ी दौड़ रही है।

जाहिरा तौर पर, यहां के आम मेहनतकश अवाम के लिए अब कोई भी उम्मीद इस व्यवस्था से नहीं रह गई है—चाहे महज एक राज्य का सवाल हो या पूरे देश का। इन्हीं अर्थों में लुटेरों ने अपने उत्तरांचल का गठन भी कर लिया है। आम जनता ने जिस खुशहाल उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, वह संघर्ष अभी भी जारी है। यह संघर्ष पूंजीवादी-साम्राज्यवादी पूरे निजाम से है, इसलिए यहां की आम जनता का संघर्ष भी पूरे देश की आम मेहनतकश अवाम के संघर्ष का हिस्सा है।

जनता सही मुद्दे के लिए संघर्ष न कर सके, इसलिए केन्द्र व राज्य की सभी पूंजीवादी चुनावी पार्टियां—चाहे सरकार में हों या विपक्ष में—आम जनता को साम्प्रदायिकता व जातिवाद-क्षेत्रवाद की घिनौने राजनीति में बांटने का ही काम करती हैं। कोई हिन्दू-मुसलिम के नाम पर बांटता है, तो कोई अगड़ा-पिछड़ा के रूप में तो कोई पहाड़ी-देशी के रूप में। भू-अध्यादेश भी ऐसा ही सरकारी तोहफा है जिसमें पूंजीपतियों-भूमाफियाओं का हित तो सुरक्षित है, लेकिन यहां की जनता के बीच पहाड़-मैदान की खाई और गहरी हो गयी।

आज पूरी दुनिया में दो ही जातियां हैं, दो ही मजहब हैं—एक अल्पसंख्यक पूंजीवादी लुटेरों का और दूसरी बहुसंख्यक कमेरों का। लुटेरे एकजुट हैं, आक्रामक हैं जबकि कमेरे बंटे-बिखरे हुए हैं इसलिए वे लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। आम जनता के मुक्तिकामी संघर्षों के एक क्रान्तिकारी केन्द्र के न होने के कारण उनके संघर्ष बार-बार बिखर जा रहे हैं, या फिर उसका फल भी पूंजीपतियों की सेवक ये मक्कार पार्टियां ही उठा ले रही हैं और जनता ठगी रह जाती है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद भी यही हुआ। राज्य गठन के तीन वर्षों का लेखा-जोखा भी यही प्रमाणित करता है।

जब मजदूर असंगठित हों तो उन्हें बात-बात पर अपमान सहना पड़ता है!

कण्ट्रोल एंड स्विचगियर कम्पनी में सुपरवाइजर-मैनेजर की बदजुबानी

पूंजीवादी व्यवस्था सड़क पर गरीब जनता के ऊपर लट्ठ भांजने की जो जिम्मेदार हवलदार-दरोगा को सौंपती है, वैसी ही जिम्मेदारी पूंजीपति कारखाने में सुपरवाइजर-मैनेजर को सौंप देता है।

यह सच है कि जब मेहनतकश असंगठित होते हैं तो थाना-कारखाना दोनों के ही हवलदार-दरोगा ज्यादा बेलगाम और बदजुबान हो जाते हैं।

इस सच्चाई के कुछ दिलचस्प उदाहरण इस संवाददाता को मिले, जब एक कारखाने के कुछ मजदूरों से उनके काम की परिस्थितियों के बारे में बातचीत हो रही थी। कंट्रोल एंड स्विचगियर कं. औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर-8 प्लाट न. 7-8 में स्थित है। इसी कंपनी के एक मैनेजर के कई किस्से मजदूरों ने सुनाये। उनका एक हिस्सा उन्हीं की जुबानी यहां प्रस्तुत है–

कंपनी के एस.एफ.यू. डिपार्टमेंट में 25-26 की उम्र का एक मैनेजर 5-6 महीने पहले आया है। मैनेजर कुछ खिलाड़ी टाइप का है। कुछ समय कराटे-फराटे सीख कर हाथ-पैर चलाना सीख गया होगा। बस फिर क्या है बंदा हवा में रहने की कोशिश करने लगा। अपने से कमजोर को पैंट की बैल्ट से पकड़ कर दोनों हाथों से ऊपर उठा लेना अपने उल्टे हाथ की बात समझता है। अपने हाथ में दूसरे का हाथ पकड़ कर जोर से उंगलियों को दबाना, कंधे पर जोर से हाथ मारना इस तरह ताकत की आजमाइश करता रहता है। जिसको मर्जी बेटा कह देता है। मजदूरों को गेट से बाहर करने की धमकी देता है रहता है। अपना दबदबा बनाने के लिए छोटी-छोटी बातों पर बाहर खड़ा करने की धमकी देना अपना कर्तव्य समझता है। यहां तक कि दूसरे डिपार्टमेंट के मजदूरों की फाइल जबर्दस्ती मांगता है। एक दिन दूसरे डिपार्टमेंट के 'क्वालिटी' चेक करने वाले मजदूर से उसके काम की फाइल मांगने लगा और कहने लगा या तो फाइल ऐसे ही दे दे, नहीं तो दूसरा तरीका भी मेरे पास है। जिस तरह देगा, उसी तरह ले लूंगा। मुझे सभी तरीके आते हैं। मजदूर परमानेंट था और काफी पुराना था, वह भी जवाब देने लगा। देखिए, सर! आप मेरे डिपार्टमेंट के नहीं हैं, आप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा मैनेजर मांगेगा तो बीस बार दिखाऊंगा। आप अपने काम से मतलब रखिए। मैनेजर और गुस्से में हो गया। कहने लगा अपनी औकात में रह, नहीं तो बाहर भी मिलेगा। दोनों जोर-जोर से बोलने लगे। एक-दूसरे को मारने में कुछ ही देरी थी, शुक्र है यह नौबत नहीं आई। मजदूर ने कहा–सर आप फैक्ट्री के मालिक नहीं हो। मैनेजर बोला–हां, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, यहां मेरी ही चलेगी। अब चुप रह, नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। आज तो छुट्टी हो गई है, कल देखूंगा तू कैसे नहीं फाइल देता। मजदूर गलती पर नहीं था, इसलिए मामला दब गया। अगले दिन उसे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन उसका गुस्सा किसी दूसरे पर उतारने की कोशिश करने लगा।

एक मजदूर की टेबल के नीचे कागज के दो-चार टुकड़े गिरे हुए थे। कहने लगा–ये कागज यहां क्यों गिरा रखे हैं? तुम बहुत गंदगी फैलाते हो, आज के बाद मुझे कागज यहां नहीं मिलने चाहिए। मजदूर ने कहा–सर, मैं काम यहां कर रहा हूं, तो कागज कहां डालूंगा? थोड़ी देर में स्वीपर आएगा, इनको उठा ले जाएगा या फिर आप डस्टबिन मंगवा दो। मैनेजर चिल्लाया–अरे, पहले अपने पास पॉलीथिन रख कर उसमें डालने की आदत डाल। डस्टबिन बाद में मंगवाएंगे। उस मजदूर ने कहा–सर हम बच्चे नहीं हैं कि आदत डालने की जरूरत पड़े ताकि कचरा बाहर न गिर जाये और पागल भी नहीं। मैनेजर का गुस्सा सातवें आसमान पर था–बस चुप रह! जुबान मत लड़ा, नहीं तो बाहर मिलेगा! मजदूर को यह बात बुरी लगी वह भी बोला–सर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा करोगे तो इंक्रीमेंट रोक सकते हो। तुझे फिर देखूंगा, कहते हुए उस वक्त तो मैनेजर चला गया। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर से आकर कहने लगा कि इस वर्कर का इंक्रीमेंट रोक दो। अबकी बार नहीं लगना चाहिए, और जो हम कंपनी में हर महीने स्टार चुनते हैं उसमें भी इसका नाम लिख कर नहीं भेजना। यह बहुत बदतमीज है। इतने में सुपरवाइजर ने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी–अच्छा सर जी, ऐसा ही होगा! इन लोगों ने तो हमारा खून पी लिया है। अब हमें और सख्त होना पड़ेगा। वे दिन गये जब मजदूरों की यूनियन थी और इनकी चलती थी। अब तो हम इनकी नाक में लट्ठ फंसा देंगे। अब हम साले किसी हरामखोर से नहीं डरते हैं।

एक दिन उसी सुपरवाइजर की एक मजदूर के साथ झड़प हो गई। बात यह थी कि कंपनी में हर रोज ओवरटाईम लगता है। सभी को रोका जाता है। वह मजदूर 'हाफ डे' मतलब लंच टाइम से ड्यूटी आया था और वह भी ओवर टाइम के लिए रुक गया। वर्कर काफी पुराना था, तनख्वाह बहुत कम थी। दूसरी बात, सुपरवाइजर ने सबके बीच खड़े हाकर यह कह दिया था कि ओवरटाइम सभी का है, जिनमें वह मजदूर भी खड़ा था। जब छुट्टी से आधा घंटा ऊपर चला गया तो सुपरवाइजर ने उस मजदूर से कहा–तुम अब घर जाओ। तुम्हारा ओवरटाइम नहीं है। मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा–सर, अब मैं नहीं जाऊंगा, आपने छुट्टी से पहले क्यों नहीं बताया था। मेरे से आधा घंटा ज्यादा काम करा कर अब मुझे घर भेज रहे हो। इसी बात पर उनमें बहस हो रही थी, यहां मजदूर की कोई गलती नहीं थी। इतने में मैनेजर आया और बोला–अरे तमीज से बात करो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हो। इसका मतलब हमारी कोई भी इज्जत नहीं है। आज के बाद मुझे कोई भी लड़ता मिला तो गेट से बाहर कर दूंगा। तमीज सीख लो कि अपने बॉस से कैसे बात की जाती है। उस दिन वह मैनेजर सभ्यता सिखा रहा था।

इसके कुछ समय बाद इस मैनेजर ने एक कैजुअल मजदूर पर अपना रोब जमाया। बात यह थी कि लंच टाइम में दो कैजुअल मजदूर आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। मैनेजर ने एक मजदूर को अपने पास बुलाया और बोला–तू बहुत ज्यादा दांत दिखाता रहता है। अपनी औकात में रहा कर, नहीं तो तेरे दांत निकाल दूंगा। मजदूर ने कहा–सर मुझे यह तो बताओ मेरी गलती क्या है? हम तो आपस में बात करके हंस रहे थे। मैनेजर के नथुने फूलने लगे–अरे, कुछ शरमाने की कोशिश कर। मजदूर बोला–सर, शर्म किस बात की करूं, कुछ तो बताओ! बात को पूरी खोल क्यों नहीं देते। मैनेजर और गुस्से में होकर बोला–खोलने को क्या पैंट खोलूं या उस से भी पीछे जो है, वह खोलूं। मजदूर सकपकाया–नहीं सर, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी गलती पूछ रहा हूं। मैनेजर बोला–साले क्या और भी गलती करने की इच्छा है। सिर्फ तू एक बार यह कह दे कि आप मेरे बॉस नहीं हो। मैं तेरे यहीं दांत निकाल दूंगा। मजदूर बहुत दूर मध्यप्रदेश का था, कैजुअल में 6 महीने के लिए रखा गया था। वह डर गया–नहीं सर, मैं यह कैसे कह सकता हूं कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। मैनेजर गुस्से से फनफनाता अपनी मैनेजरी झाड़ने लगा–कल से तू फैक्ट्री मत आना! साले तू सबसे बदतमीज है, तेरी शक्ल भी सबसे भद्दी है। मैनेजर ने परमानेंट मजदूरों का गुस्सा उस कैजुअल पर उतार लिया।

ऐसे ही कई और किस्से मजदूरों ने सुनाये। इन मजदूरों ने माना कि एकता की कमी के चलते ही आज साहबों की गालियां और धमकियां सुननी पड़ रही हैं। इस नये मैनेजर जैसों ने शायद ही कभी मजदूरों की एकता की ताकत देखी-जानी हो। एक मजदूर का कहना था कि अभी मैनेजर जी चढ़ते हुए और ढलते हुए सूरज की रोशनी में अपनी बड़ी सी परछाई देखकर अपने को विशाल समझने लगे हैं। इन्होंने अभी दोपहर के सूरज की रोशनी में अपनी परछाई को नहीं देखा, वह पैरों के तले होती है।

मैको प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में 80 मजदूरों की छंटनी

एक मजबूत मजदूर आंदोलन के बिना यह सिलसिला थमेगा नहीं

बिगुल संवाददाता

सोनीपत। हरियाणा के इस शहर के सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मैको कम्पनी ने सभी श्रम कानूनों को ताक पर रखते हुए बगैर किसी कारण, बिना किसी नोटिस के इस कम्पनी के 80 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैको कम्पनी में लगभग 200 मजदूर काम करते थे। इस कम्पनी में 'पिस्टन-पिन' बनता है जो मोटर साइकिल, थ्री व्हीलर व ट्रैक्टर में डाला जाता है। यह कम्पनी यहां पर पिछले 30-35 साल से स्थापित है। इस कम्पनी का इतिहास ही मजदूरों के अपार-शोषण का इतिहास है। यहां कभी भी यूनियन नहीं बनने दी गई, यदि कोशिश भी की गई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिला प्रशासन से लगातार पैसे के बल पर अच्छे सम्बन्ध रहे हैं मालिक के, जिसके कारण मजदूरों पर दबाव बनाने में पुलिस का सहयोग भी मिलता रहा है। यह कम्पनी लगातार मुनाफे में रही है जिसके पीछे मजदूरों से हाड़तोड़ मेहनत व नाममात्र का वेतन एक कारण तो रहा ही है बल्कि प्रशासन की मिलीभगत से लाखों की बिजली व टैक्स चोरी के लिए मालिक कुख्यात हैं। 2002 तक कम्पनी मजदूरों को 4800 रुपये बोनस दे रही थी, लेकिन 2003 में यह बोनस मात्र 2000 कर दिया, और 80 मजदूरों को 4 दिसम्बर को बाहर निकाल दिया गया। इसके पीछे वही घिसे-पिटे तर्क देते हुए मालिक ने कहा कि कम्पनी का मुनाफा घट गया है। जैसा कि इस पूंजीवादी समाज में अक्सर होता आया है कि मुनाफा बटोरे मालिक और घाटे में मार पड़े मंजदूर पर। ये सभी मजदूर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे उन्हें स्थायी नहीं किया गया था और न ही कोई अतिरिक्त सुविधा थी, जब तक वे काम के थे उनको रखा और जब बोझ लगे तो बाहर किया यानी कि 'निचोड़ो और फेंको'।

साथियो, पूरे देश के मजदूरों की यही हालत है। छंटनी, तालाबंदी और ठेकेदारी की चाबुक सटाक-सटाक मालिक लोग पूरे देश में चला रहे हैं, नेता-अफसर भी उन्हीं के राग में राग मिला रहे हैं। 'मैको' जैसी छोटी-बड़ी कम्पनियों में रोज कहीं न कहीं यह चाबुक पूरे देश में चलता रहता है और 1990 की सरकार की नई आर्थिक नीतियों के बाद तो यह चाबुक बहुत तेजी से चल रहा है और करोड़ों मजदूरों को लहूलुहान कर चुका है।

यूनियन और श्रम कानून जो मजदूरों के अधिकारों के सुरक्षा कवच समझे जाते थे, वे जर्जर हालत में हैं। मालिक वर्ग के साथ खड़े ये नेता और अफसर नये-नये कानून बनाकर मजदूरों के रहे-सहे कवचों को पूरी तरह फाड़कर मजदूरों की खाल नोचने और खून निचोड़ने के लिए मालिकों को पूरी छूट दे चुके हैं। वैसे तो मालिक वर्ग पहले से ही श्रम कानूनों को ताक पर रखकर व यूनियनों को कुचलकर व जेबी यूनियनें बनाकर मजदूरों की खाल नोचता रहा है लेकिन जब नया श्रम कानून इसकी खुली इजाजत दे देगा तो यह कल्पना की जा सकती है कि मजदूरों, मेहनतकशों का जीवन कितना संकट में पड़ जायेगा। चुपचाप काम करो। हर जुल्म, शोषण, अपमान सहन करो।

हालत बेहद तेजी से मजदूर विरोधी बनते जा रहे हैं। जीवन भयानक होता जा रहा है भविष्य। की गारंटी नहीं और तो और इन हालात के विरुद्ध तगड़े विरोध की आवाज भी बुलंद होती दिखाई नहीं दे रही। कुछ नकली लाल झण्डे की यूनियनें इन मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध रस्म अदायगी के रूप में रैली-प्रदर्शन करके मजदूरों को भरमाने का ही काम कर रही हैं। कोई व्यवस्थित और सही मजदूर संघर्ष की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। पूरी तरह से एक सही और नई शुरुआत करने की जरूरत है क्योंकि मरने या लड़ने में से सही इंसान लड़ने को चुनता है और विपरीत परिस्थितियों को चुनौती मान कर संघर्ष का रास्ता खोजता है! आज यही करने की जरूरत है।

हमें पूरे मजदूर आंदोलन के इतिहास को समझना होगा। उसकी कामयाबी व कमजोरियों को ईमानदारी से चिन्हित करना होगा। नये सबक व नये रास्ते निकालने होंगे। नये हौसले व नये नारे बुलंद करने होंगे। यह कठिन जरूर है लेकिन एकमात्र यही रास्ता है।

वर्ष 2003 : उदारीकरण के दौर का एक और काला वर्ष

(पेज 12 से आगे)

अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। यही नहीं, तमिलनाडु के पौने तीन लाख हड़ताली राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों की बर्खास्तगी पर तो ये सभी यूनियनें खामोश रही हीं, हड़ताल पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के बेहद खतरनाक फैसले पर भी ये कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। ये महज अखबारी बयानबाजी करते रहे और राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रधानमंत्री की चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर और भोज-भात खाकर अपनी-अपनी मांदों में छुपकर बैठ गये।

दुनिया के पैमाने पर वर्ष 2003 में, आतंकवाद के सरगना अमेरिका की दादागिरी अपने चरमोत्कर्ष पर थी और ब्रिटेन के साथ मिलकर, पूरी दुनिया में जबर्दस्त विरोध के बावजूद इसने इराक में भयानक रूप से कत्लेआम मचाया। लेकिन, विश्व विजेता बनने और तेल पर एकाधिकार कायम करने के इसके मंसूबों को लगातार चुनौती देते हुए इराकी जनता का प्रतिरोध युद्ध लगातार जारी है। उधर कानकुन में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा।

कुल मिलाकर, देशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बढ़ती जकड़बन्दी का, निजीकरण-छंटनी-तालाबंदी का मजदूर विरोधी फैसलों के लिए न्यायपालिकाओं की कुख्याति का, भ्रष्टाचार के कुछ और नये कीर्तिमान बनाने का, तरह-तरह के काले कानूनों के लागू होने, तथाकथित समीक्षा के बाद दमनकारी पोटा को बरकरार रखने व दमन का पारा तेज होने का, साम्प्रदायिक धर्मोन्माद बढ़ाने का, युद्धोन्माद का व आम जनता की तबाही-बर्बादी का एक और काला वर्ष 2003 भी गुजर गया।

–एम. रंजन

काकोरी के शहीदों का बलिदान दिवस (19 दिसम्बर)

रुद्रपुर। काकोरी काण्ड के बहादुर क्रान्तिकारियों का 76वां शहादत दिवस 'नौजवान भारत सभा' व 'बिगुल मजदूर दस्ता' ने एक नए संकल्प के साथ मनाया। कार्यक्रम का आयोजन खेड़ा मोहल्ला स्थित अशफाकउल्ला खां पार्क में किया गया था। शुरुआत शहीद राम प्रसाद बिस्मिल्ल व अशफाक उल्ला खां के चित्रों पर वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मूर्ति सिंह द्वारा माल्यार्पण से हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. प्यारेलाल ने की।

शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं और मुहल्लावासियों ने मशाल जुलूस निकाल कर लोगों को शहीदों की कुर्बानियों की याद दिलायी। यह कार्यक्रम साझी शहादत-साझी विरासत के रूप में व हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया गया। सभा को सम्बोधित करते हुए श्री मूर्ति सिंह ने कहा कि हमारे साथियों ने एक समतामूलक समाज के लिए कुर्बानियां दी थीं लेकिन देश धर्म-जाति व भाषा के नाम पर बांटने वाले नेताओं के चंगुल में फंस चुका है।

आज बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव पर बात करते हुए डा. प्यारे लाल ने कहा कि काकोरी के अमर शहीद उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के सेनानी थे। वे समाज में व्याप्त हर तरह के जुल्म-शोषण व अन्याय का खात्मा करने के साथ एक शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे साम्प्रदायिकता के कट्टर दुश्मन थे। आज साम्प्रदायिक धर्मोन्माद के इस दौर में बिस्मिल, अशफाक जैसे क्रान्तिकारी की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। वक्ताओं का मुख्य जोर साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा करने वाली तमाम नामधारी चुनावी पार्टियों की कारगुजारियों पर रहा।

वक्ताओं ने कहा कि जब देश में बेरोजगारी-छंटनी-तालाबंदी-लूट और तबाही का कहर बरपा करने वाली नयी आर्थिक नीतियों को लागू करने की तैयारी हो रही थी तो मंदिर-मस्जिद विवाद उठाया गया, नीतियों के अमल के समय बाबरी मस्जिद विध्वंस से धर्मोन्माद के एक नये दौर की शुरुआत हुई और जब जनता बेरोजगारी, छंटनी आदि के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी तब गुजरात में वहशीपन व बर्बरता के सबसे खतरनाक दौर की शुरुआत हुई। यह अलग से स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि देश को जातीय और मजहबी फसाद में उलझाने वाले ये वही सत्ताधारी हैं जो अमेरिका, जापान व विदेशी लुटेरों के तलुए चाटते हैं। सभा को गोपाल कृष्ण, अशोक शर्मा, शकील, अश्विनी आदि ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर निकाले गये पर्चे का केन्द्रीय नारा था 'साम्प्रदायिक फासीवाद मुर्दाबाद, जनता की एकजुटता जिन्दाबाद।' इस पर्चे में कहा गया है कि–"साम्प्रदायिकता पूंजीवादी-राजनीतिक तंत्र का कचरा है। इसे मेहनतकशों की एकता के लोहे के झाड़ू से बुहारकर हिन्द महासागर में फेंक देना होगा।"

कार्यक्रम के दौरान खेड़ा मुहल्ले के बच्चों ने दो नाटक 'तमाशा' व 'बेकरीवाला' प्रस्तुत किया। वर्तमान व्यवस्था की संसदीय राजनीति पर कटाक्ष करते हुए 'नौजवान भारत सभा' व 'बिगुल मजदूर दस्ता' के कार्यकर्ताओं ने 'हवाई गोले' नाटक प्रस्तुत किया। जिसमें संसद के जूतमपैजार और कुत्ताघसीटी को हूबहू सड़क पर उतारा गया।

नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने 'बिस्मिल' की मशहूर नज्म 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है' प्रस्तुत की।

काकोरी काण्ड के अमर सेनानी शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद अशफाकउल्ला खां के चित्रों सहित निकाले गये पोस्टर में लोगों को झकझोरते हुए कहा गया है– *"उठो-उठो सो रहे हो नाहक, पयामे बागे जरस तो सुन लो। बढ़ो कि कोई बुला रहा है, निशाने मंजिल दिखा-दिखाकर।"*

इस अवसर पर क्रान्तिकारियों के विचारों और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर केंन्द्रित पोस्टर प्रदर्शनी व पुस्तक प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी जो लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही।

शहीद अशफाकउल्ला खां के विचारों को विस्तार देती हुई एक पुस्तिका का प्रकाशन भी 'नौजवान भारत सभा' ने किया जिसका विमोचन श्री मानवेन्द्र सिंह ने किया।

कार्यक्रम का समापन 'काकोरी के शहीद अमर रहें', 'जाति-धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो' आदि नारों के साथ हुआ।

खेड़ा स्थित अशफाकउल्ला खां पार्क में दो वर्ष पूर्व मोहल्लेवासियों ने मिलकर अशफाकउल्ला की मूर्ति लगवाई थी जिसे अनावरण से पहले ही कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करके नाले में फेंक दिया था। अशफाक की मूर्ति के साथ यह बर्ताव ठीक वैसा ही था जैसा पटना, जयपुर में शहीदे आजम भगतसिंह की मूर्ति के साथ हुआ था। इस घटना को लेकर नागरिकों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने मामले को ठण्डा करते हुए मूर्ति पुनर्स्थापना की घोषणा कर डाली। आज दो साल बाद भी कोई मूर्ति नहीं लगायी गयी थी। पार्क कूड़े घर के रूप में तब्दील हो चुका था। 'नौजवान भारत सभा' व खेड़ावासियों ने मिलकर नगरपालिका अध्यक्ष को पार्क के सौन्दर्यीकरण व मूर्ति पुनर्स्थापना को लेकर ज्ञापन दिया था और 19 दिसम्बर काकोरी काण्ड के शहादत दिवस से पूर्व पार्क का सौन्दर्यीकरण करवाने की मांग की थी। नगरपालिका के भाजपायी अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल से तत्काल लम्बे-चौड़े वादे कर डाले लेकिन आशंका को सही साबित करते हुए हर मौके पर वादाखिलाफी करनेवाले नेता ने कोई सुधार कार्य नहीं करवाया। इसे लेकर मोहल्लेवासियों में रोष व्याप्त है, कार्यक्रम के साथ ही इस बात का ऐलान भी किया गया कि जब तक अशफाकउल्ला खां पार्क का सौन्दर्यीकरण व मूर्ति पुनर्स्थापना नहीं हो जाती है यह संघर्ष जारी रहेगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन जाता क्योंकि आज सफाई सिर्फ पार्क की ही नहीं बल्कि बदबूदार और दमघोंटू हो चुकी इस पूरी व्यवस्था की करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ 'मजदूर सत्याग्रह' अभियान

बिगुल संवाददाता

खटीमा (ऊधमसिंह नगर) क्षेत्र की विभिन्न मजदूर-कर्मचारी यूनियनों-संगठनों के साझा मंच 'संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा' की ओर से खटीमा के संजय पार्क में सभा का आयोजन हुआ। यह सभा उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबन्ध के आदेश के विरोध में मोर्चे द्वारा चलायेग जा रहे 'मजदूर सत्याग्रह' अभियान के अन्तर्गत की गयी।

सभा में वक्ताओं ने कहा कि विगत 13 वर्षों से उदारीकरण के नाम पर निजीकरण-छंटनी-तालाबंदी और लम्बे संघर्षों के दौरान प्राप्त श्रम कानूनी अधिकारों को छीनने का जो क्रम सत्ताधारी चला रहे हैं, न्यायपालिकाएं भी उसमें खुलकर अपनी पारी खेल रही हैं। हड़ताल के बुनियादी अधिकार को छीनना उसकी कड़ी का एक खतरनाक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों में निलम्बन के बाद पुनर्बहाली पर पुराने देयकों के भुगतान को गैर जरूरी बताता है, 'समान काम पर समान वेतन' के अधिकार को खारिज करता है, हड़तालियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार को आदेश देता है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय प. बंगाल में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का और पटना उच्च न्यायालय न्यायपालिका पर उठनेवाली उंगली को काट लेने का फरमान जारी करता है।

वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उदारीकरण-निजीकरण की घोर मजदूर-विरोधी, व्यापक जन-विरोधी और देशद्रोही नीतियों पर अमल करके पूंजीवादी आर्थिक ढांचे को नयी शक्ल देने का काम अब फैसलाकुन दौर में है।

लगातार छंटनी, यार्न प्लांट के मजदूरों पर हिसाब ले लेने के मानसिक दबाव और प्रबन्धन की तानाशाही की तीखी भर्त्सना की गयी।

सभी वक्ताओं ने अलग-अलग यूनियनों के बंटवारे, जाति-क्षेत्र-धर्म के नाम पर व सरकारी-निजी क्षेत्रों के बंटवारे की दीवारों को तोड़कर एकजुट होने का आह्वान किया। सभा की शुरुआत में खटीमा स्थित खटीमा फाइबर्स लि. के मजदूर राकेश की विगत माह प्रबंधन के असुरक्षात्मक प्रावधानों के कारण डाइजेस्टर में गिर कर हुई मौत पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी।

सभा की अध्यक्षता हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन के आर सी खन्ना व संचालन बिगुल मजदूर दस्ता के मुकुल ने किया। सभा में ईस्टर इण्डस्ट्रीज मजदूर संघ, ईस्टर इण्डिया इम्पलाइज यूनियन, पोली प्लैक्स इम्पलाइज यूनियन, उत्तरांचल ऊर्जा कामगार संगठन, बिजली मजदूर संघ, श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन आदि के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रकट किये। सभा के माध्यम से ईस्टर इण्डस्ट्रीज की दो विरोधी यूनियनों को एक मंच पर लाने की भी शुरुआत हुई।

इससे पूर्व 'मजदूर सत्याग्रह' के तहत एल.आई.सी., विलासपुर (रामपुर) एफ सी आई रुद्रपुर में सभाओं का क्रम चलने के साथ ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न यूनियनों–पंतनगर कर्मचारी संघ, श्रमिक कल्याण संघ पंतनगर, पंतनगर वर्कर्स यूनियन व उ.प्र. बीज एवं तराई विकास निगम कर्मचारी संघ को एक मंच पर लाकर मोर्चे ने मजदूरों की एक बड़ी सभा की थी।

बाद में पंतनगर में संघर्ष के लिए यूनियनों का एक मोर्चा भी गठित हुआ।

सरकारी कंपनियों को बेचने का सिलसिला जारी
अब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. की बारी

कार्यालय संवाददाता

लखनऊ। आम जनता को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अपने देश की सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। जिस देश में दवा-इलाज के अभाव में हर साल हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हों, सरकारी अस्पताल सिर्फ दिखाने के लिए हों, बाजार में आसमान छूती कीमत की दवाएं आधी आबादी की पहुंच से बाहर हों, वहां पर सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मुनाफाखोरों को खुली लूट के लिए बुला रही है। बेहयाई के साथ यह अपराध सरकार देश के विकास के नाम पर कर रही है।

सरकारी दवा कंपनी आईडीपीएल के बाद अब एच.ए.एल. (हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.) को बेचने की तैयारी चल रही है। एच.ए.एल के कारखाने में पेनसिलीन और जेंटामाइसिन जैसी जीवनरक्षक दवायें बनती हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण ये दवायें आज चार-छः रुपये में मिल जाती हैं, जबकि इन्हीं दवाओं को बहुराष्ट्रीय या निजी कंपनियां तीन गुना दाम पर बेचती हैं। जाहिर है कि मुनाफाखोर के खूनी पंजों में इस सरकारी कंपनी के चले जाने के बाद ये जीवनरक्षक दवायें गरीब की पहुंच से बाहर हो जायेंगी।

देश में जब से भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं तब से एक-एक कर जनता की गाढ़ी कमाई से खड़े किये गये सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का सिलसिला चल पड़ा है। ताजा कोशिश केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने की है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पुणे स्थित जीवनरक्षक दवाएं बनाने वाली सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स को सन फार्मा के हाथों बेच दिया जाये। सालाना 110 करोड़ रु मूल्य का उत्पादन करने वाली यह कंपनी महज सवा दो करोड़ रुपये की सालाना लीज पर सन फार्मा को देने की गुपचुप तैयारी की जा चुकी है।

800 करोड़ रुपये के उपक्रम हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के कुछ हिस्से को सरकार 1995 में हालैंड के मैक्सजीबी कंपनी को पहले ही सौंप चुकी है। समझौते के अनुसार मैक्स जीबी को मशीनों के किराये के रूप में 17.5 करोड़ सालाना तथा कर्मचारियों के वेतन के 80 लाख प्रतिमाह तथा बिजली आदि के बिल का भुगतान करना था। समझौते के तहत जो लाभ होगा उसमें दोनों कंपनियों की बराबर की हिस्सेदारी थी। लेकिन मैक्सजीबी ने ज्यादातर भुगतान नहीं किये और आज की तारीख में उस पर एच.ए.एल का 80 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी उगाही के लिए मुंबई हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।

एच.ए.एल के 20 करोड़ रुपये विभिन्न राज्य सरकारों पर दवा बिक्री के बकाया हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स मजदूर संघ के नेताओं का कहना है कि कारखाना अब भी लाभ में चल रहा है।

संघ के नेताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध प्रतीकात्मक घंटनाद के रूप में किया है। इस फैसले के विरोध में मजदूर कंपनी के गेट पर रोज सुबह ड्यूटी शुरू होने से पहले, लंच टाइम और शाम को आधे-आधे घंटे घंटनाद करके विरोध जता रहे हैं। एन.पी.एच.ए.एल मजदूर संघ ने विरोध का जो मरियल रवैया अख्तियार किया है उससे आज के दौर में अर्थवादी ट्रेड यूनियनों का बेमानीपन ही जाहिर हो रहा है। इस कारखाना केंद्रित लड़ाई का भविष्य भी वही नजर आ रहा है जो पिछली सभी ऐसी लड़ाइयों का हुआ है।

एक बार फिर आज के दौर की यह सच्चाई ही उजागर हो रही है कि जब तक मजदूर आंदोलन का नया क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं उभरकर सामने आयेगा तब तक मजदूर आंदोलन फैसलाकुन लड़ाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ पायेगा।

भविष्यनिधि में घोटाला-दर-घोटाला

इन डकैतियों पर मजदूर कब तक मूकदर्शक बना रहेगा?

बिगुल संवाददाता

घोटाला-दर-घोटाला की कड़ी में, कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) में घोटाले का एक और पर्दाफाश हुआ है। मजदूरों के खून-पसीने की कमाई का अंश भविष्य के लिए सुरक्षित होने की जगह किसी 'ब्लैक होल' में समा गया है।

खातों की हेरा-फेरी से 563 करोड़ रुपये गायब हैं। इस घटना पर ई पी एफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सी बी टी) के बैठक में श्रम मंत्री साहिब सिंह वर्मा घड़ियाली आंसू बहाकर अपने को पाक साफ दिखलाने का प्रयास करते रहे। बंगलौर में एक घपले का मामला खुलने के बावजूद कर्मठ संघी इस श्रम मंत्री ने महज यह कहकर इतिश्री कर ली कि हो सकता है कि यह किसी घपले का परिणाम हो।

563 करोड़ रुपये का यह एकमुश्त बड़ा घोटाला है, लेकिन मजदूरों व कम्पनी/विभाग से वेतन के 12-12 प्रतिशत की कटौती कर भविष्य निधि के नाम से जमा इस राशि के छोटे-छोटे घोटालों की लम्बी फेहरिस्त है, जिसका कहीं कोई अता-पता नहीं है। मजदूरों के वेतन से उनका हिस्सा काट लेने के बावजूद कई कम्पनियां, यहां तक कि सरकारी कारखानों-निगमों तक ने पी एफ खाते में कई-कई वर्ष से धनराशि जमा नहीं की हैं। यहां तक कि मजदूरों के हिस्से से प्राप्त राशि भी खुद ही इस्तेमाल कर जाती हैं। आये दिन कई कम्पनियां पी एफ खाते का पैसा हड़प कर भाग भी चुकी है।

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल की निगम की कताई मिलों में, जिनमें से आज ज्यादातर बन्द हो चुकी हैं। मजदूर भुखमरी का शिकार है। कई वर्षों से पी एफ खाते में पैसा जमा ही नहीं हुआ है। इन दो राज्यों में से महज उत्तर प्रदेश में घिसटते हुए चल रही कताई मिलों में तो मजदूरों के वेतन से काटने के बावजूद 5-6 वर्षों से उनके खातों में राशि जमा नहीं हो रही है।

इसी प्रकार उत्तरांचल राज्य के नैनीताल जिले में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की घड़ी निर्माता कम्पनी एच एम टी पर पी एफ खाते का ताड़े चार करोड़ रुपये का बकाया है। उत्तरांचल परिवहन निगम पर 52 लाख रुपये का बकाया है। यहां निजी क्षेत्र के बन्द करके भागे कारखानों में किस्टल क्रेडिट कार्पोरेशन पर एक करोड़, बेलवाल स्पिनिंग मिल पर 90 लाख, मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये बकाया है। देश भर की यह पूरी सूची बहुत लम्बी-चौड़ी है जिसके सामने खातों की हेराफेरी से हुआ 563 करोड़ रुपये का घोटाला बौना साबित होगा।

भविष्य निधि के माध्यम से मजदूरों पर सीधी डकैती का एक और रूप मौजूद है। नियमानुसार तमाम कम्पनियों में कैजुअल या ठेके के तमाम दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का पी एफ काटा जाता है। ऐसे मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है जो चार-छह महीने एक जगह तो फिर दूसरी जगह काम करते हैं। ऐसे में अमूमन तो पी एफ का ज्यादातर पैसा कम्पनियां या फिर ठेकेदार ही हड़प जाते हैं। जो धनराशि पी एफ खाते में जमा भी होती है वो मजदूरों की छोटी-छोटी राशि होती है और फालतू के भागदौड़ और पचड़ों में फंसने अथवा जानकारी न होने के कारण मजदूर वह राशि वापस निकाल नहीं पाता है। ऐसे में प्रतिवर्ष मजदूरों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये भविष्य निधि निगल जाता है जिसका कहीं कोई अता-पता नहीं चलता।

कुछ बड़ी देशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ट्रस्ट बनाकर पी एफ का पैसा अपने पास ही रखती हैं जिसका इस्तेमाल प्रायः वे अपने व्यापार व मुनाफे के लिए करती हैं।

भविष्यनिधि कार्यालय का दस्तूर बन चुका है कि जब कोई मजदूर जरूरत पड़ने पर अपने इस खाते से बतौर कर्ज भी रुपया निकालना चाहता है अथवा नौकरी छूटने पर हिसाब लेना चाहता है तो उसे मिलनें वाले रकम का एक हिस्सा कार्यालय में ही भेंट चढ़ाना पड़ता है, वरना फाइलों की पेचीदगी में ही वह उलझा रहता है।

इस प्रकार मजदूरों की कड़ी मेहनत के इस पैसे का मुनाफाखोर लुटेरों, उसकी अफसरशाही-नौकरशाही-बाबूशाही द्वारा जबर्दस्त रूप से बंदरबांट जारी है। इस खाते में रुपये मौजूद होने के कारण देशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ललचाती निगाहें लगी हुई हैं। और उदारीकरण के इस दौर में सरकार भविष्यनिधि का भी निजीकरण करने की फिराक में है।

आखिर देश का मजदूर कब तक लूट, गबन व खुलेआम डकैती को देखता व सहता रहेगा?

ईस्टर इण्डस्ट्रीज में मजदूर उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त ज्ञापन

क्या कारखाने की दोनों यूनियनें साथ चलेंगी?

बिगुल संवाददाता

खटीमा (ऊधमसिंह नगर)। स्थानीय ईस्टर इण्डस्ट्रीज लि. के प्रबन्धन की बढ़ती तानाशाही, छंटनी व यार्न प्लांट के समस्त 52 मजदूरों को निकालने की उसकी साजिशों के खिलाफ 'संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा' की पहल पर क्षेत्र की तमाम यूनियनों की ओर से उपश्रमायुक्त को ज्ञापन भेजा गया है, जिसी प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, श्रमायुक्त व जिलाधिकारी को भी भेजी गयी है।

ज्ञापन में लिखा है कि ईस्टर प्रबन्धन द्वारा यहां के श्रमिकों की जबरिया छंटनी के साथ ही उनका उत्पीड़न जारी है। कारखाने के कई विभागों में श्रमिकों को अक्सर बैठाकर ठेका श्रमिकों से काम कराया जाता है। प्रबन्धन ने नियमित श्रमिकों पर अपना इस्तीफा देकर हिसाब लेने का दबाव लगातार बनाये रखा है। इसी क्रम में उसने यार्न प्लांट में विगत नौ महीने से उत्पादन ठप्प कर दिया है और प्लांट के सभी 52 श्रमिकों के ऊपर हिसाब ले लेने का दबाव डाल रहा है। यही नहीं उसने कारखाने के अन्य श्रमिकों को तो इस वर्ष बोनस एक्सग्रेसिया का भुगतान किया लेकिन यार्न प्लांट के श्रमिकों को इससे वंचित रखा।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रबन्धन ने अपने तमाम हथकण्डों से स्थायी श्रमिकों की सेवायें समाप्त कर दिया हैं। एक समय जिस कारखाने में 535 स्थायी श्रमिक थे आज वहां महज 365 श्रमिक रह गयी हैं। छंटनी का यह क्रम लगातार जारी है।

ज्ञापन के माध्यम से यार्न प्लांट में उत्पादन फिर से शुरू करके श्रमिकों को पहले की भांति यथास्थान काम पर लगाने व मानसिक उत्पीड़न बन्द करने, बोनस का भुगतान करने, छंटनी पर पाबंदी लगाने व फर्जी निलम्बन व निष्कासन वापस लेने तथा 2001 से अवैधानिक रूप से 28 निलम्बित श्रमिकों व अन्य निष्कासित श्रमिकों की कार्य बहाली की मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि कारखाने में दो यूनियनों के पाट में यहां का मजदूर बुरी तरह से पिस रहा है। आशंका से ग्रसित यहां के मजदूरों की लगातार यह चाहत रही है कि दोनों यूनियनें मिलकर व ईमानदारी पूर्वक संघर्ष के लिए आगे आयें ताकि प्रबन्धन के शोषण से मजदूर मुक्त हो सकें।

'संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा' की पहल पर यहां के इतिहास की यह पहली घटना है जबकि यहां की दोनों यूनियनों ने क्षेत्र की अन्य यूनियनों के साथ यह साझा ज्ञापन भेजा है। इससे इस कम्पनी के मजदूरों में उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन अब भी सभी मजदूरों के मन में यह आशंका बनी हुई है कि क्या दोनों यूनियनें मजदूर हित में भविष्य में भी एक साथ संघर्ष की बागडोर संभालेगी?

अंतरिम पेंशन फण्ड नियामक व विकास प्राधिकरण का गठन

अब पेंशन का भी निजीकरण

बिगुल संवाददाता

देश व दुनिया के मुनाफाखोरों की शिकारी निगाहें हर उस चीज पर हैं, जहां से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पीटा जा सकता है। बीमा व बैंक के निजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, सरकारी उपक्रमों को औने-पौने दामों पर देशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं के हाथों में सौंपने के क्रम में ही अब सरकार मजदूरों के सबसे अहम पेंशन फण्ड को भी इन लुटेरों को सौंपने जा रही है।

भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार के मजदूर विरोधी एक और फैसले बाद 1 जनवरी 2004 से 'अंतरिम पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण' (पी एफ आर डी ए) का गठन हो जायेगा। इसके साथ ही एक 'अंतरिम सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी' की भी स्थापना हो जायेगी, जिसे दो तीन महीने में अंतिम रूप भी दे दिया जायेगा। जनवरी में ही सरकार एक नयी पेंशन स्कीम भी पेश कर देगी।

यह अंतरिम नियामक पेंशन क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के अलावा इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा और प्रवेश के लिए न्यूनतम पूंजी की रूपरेखा भी तय करेगा। वह इस क्षेत्र में उतरने वाले फंड मैनेजरों की निविदाएं भी आमंत्रित करेगा। नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हो रही इस योजना के दूसरे चरण में सरकार निजी कम्पनियों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जायेगा।

इस योजना के लागू होने का देशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि इनमें से कई में तो 'फण्ड मैनेजर' (नयी पेंशन ठेकेदार कम्पनी) बनने की पहले ही पेशकश कर दी है। 'नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड' (एन एस डी एल), सी आर ए (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) बनने की प्रबल दावेदार है। 'आई सी आई सी प्रुडेंशियल, एचडीएफसी स्टैण्डर्ड, लाइफ, प्रिंसिपल फाइनेंशियल, टेंपलटन, डीएसपी मेरिल लिंच और कोटक जैसे फंड मैनेजर नयी पेंशन स्कीम की प्रतीक्षा कर रही हैं।

दरअसल, मजदूरों के खून-पसीने की कमाई से जमा होने वाली यह धनराशि इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती है और जो बतौर 'फिक्स डिपाजिट' लम्बे समय तक पेंशन फंड में पड़ी रहती है जो बिना किसी 'रिस्क' के पूंजीपतियों के मुनाफे का जरिया बन सकती है।

गौरतलब है कि राज्य और केन्द्र की सरकारें पहले भी कई बार 'पेंशन फंड' का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बांटने अथवा अन्य मदों में करती रही है। 1996 से पेंशन को अनिवार्य बनाने के पीछे भी सरकार की यही मंशा रही है कि वह इस मद में ज्यादा से ज्यादा धनराशि इकट्ठा करके मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचाये। 'पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण' का गठन व नयी पेंशन स्कीम इसी प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

साम्राज्यवादी डाकुओं की बढ़ती लूट,
देशी सरमायेदारों की फूलती थैलियां,
मेहनतकशें की बढ़ती तबाही,
बेरोजगारी, आसमान छूती मंहगाई,
छंटनी-तालाबंदी, तबाही-बर्बादी,
काले कानून, लाठी-गोली का प्रजातंत्र,
बिकता न्याय,
अराजकता, लूटपाट, गुण्डागर्दी,
दलाली, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार,
मण्डल-कमण्डल, दंगे-फसाद,
भ्रष्ट सरकार, झूठी संसद, नपुंसक विरोध
इनसे निजात पाने की राह क्या है?

इलेक्शन या इंकलाब?

संसद-विधानसभाएं बहसबाजों के अड्डे हैं
ये पूंजीवादी राज्यसत्ता के दिखाने के दांत हैं।
पुलिस, फौज और जेल
कोर्ट-कचहरी, कानून और अफसरशाही
इसके जबड़े और पंजे हैं।

चुनावी राजनीति के मायाजाल से बाहर आओ!
क्रान्तिकारी राजनीति की अलख जगाओ!!

विशेष सामग्री

(चौंतीसवीं किस्त)

पार्टी की बुनियादी समझदारी

अध्याय -11

पार्टी के प्राथमिक संगठनों के जुझारू काम

एक क्रान्तिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रान्ति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सच साबित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी क्रान्ति का रास्ता छोड़ संसदीय रास्ते पर चलने वाली नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रान्ति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सबसे ऊपर है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, फरवरी 2001 के अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किस्तों में प्रकाशन शुरू किया है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गई श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गई थी। मार्च, 1974 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4,75,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फ्रांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नार्मन बेथून इंस्टीट्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फ्रांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है। –सम्पादक

पार्टी के प्राथमिक संगठनों को अपने सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए

अपने पांच जुझारू कामों को पूरा करने के लिए, पार्टी के प्राथमिक संगठनों को अपने सुदृढ़ीकरण को बिल्कुल पक्के तौर पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

उन्हें अपने सदस्यों के सैद्धान्तिक और राजनीतिक कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी पहल को पूरी तरह काम में लाना चाहिए। आगे की कतारों वाली लड़ाकू टुकड़ियों के रूप में पार्टी के प्राथमिक संगठनों की भूमिका को पार्टी सदस्यों के मिसाल पेश करने वाली अगुआ भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पार्टी के प्राथमिक संगठनों को अपने सैद्धान्तिक और राजनीतिक कामों को मजबूत करना चाहिए, वर्ग संघर्ष और दो लाइनों के संघर्ष की बाबत अपने सदस्यों की चेतना को लगातार ऊपर उठाना चाहिए, उनका राजनीतिक स्तरोन्नयन करना चाहिए और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी के हरेक सदस्य को सर्वहारा वर्ग का अगुआ योद्धा बनाना चाहिए, जो उत्साह और ऊर्जस्विता से भरपूर हो, और पार्टी व राज्य द्वारा सौंपे गये जुझारू कामों को पूरा करने के लिए जनसमुदायों का नेतृत्व करने में सक्रिय रूप से पहल लेनी चाहिए। पार्टी की कार्यदिशा, मार्गदर्शक सिद्धान्त और नीतियों को लागू करने में, उन्हें इन चीजों का सचेतन तौर पर अध्ययन करने और विचार विमर्श करने, उनकी मूल भावना को समझने, जिम्मेदारियों को समझने और पद्धतियों पर अध्ययन करने के लिए संगठित होनी चाहिए ताकि सदस्य पार्टी की कार्यदिशा, मार्गदर्शक सिद्धान्त और नीतियों को सचेतन तौर पर लागू करने के काबिल हो सकें। पार्टी शाखाओं को आधारभूत स्तर पर पार्टी के कामों पर उनके सदस्यों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं और सुझावों को सुनना चाहिए और उन्हें अपने विचारों को मुक्त रूप से प्रसारित करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें अपने सदस्यों के कामों से सरोकार रखना चाहिए, ऐसी स्थितियां तैयार करनी चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें, और फिर कामों की जांच करनी चाहिए; उचित मौके पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जब वे कामयाब हों और सही वक्त पर उनकी कमियां बता देनी चाहिए, साथ ही उन्हें उनके अनुभवों का समाहार करने और उनसे नतीजे निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरीके से, पार्टी सदस्यों की राजनीतिक चेतना, उनकी राजनीतिक समझ का स्तर और काम करने की उनकी क्षमता बढ़ जायेगी, और हर समय उनकी पहल खुलकर सामने आयेगी।

हमें दृढ़तापूर्वक पार्टी समूहों के काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी भूमिका को पूरी गुंजाइश मिले। पार्टी समूह पार्टी शाखा के अधीन एक जुझारू समूह होता है। जिस तरीके से पार्टी समूह अपनी भूमिका निभाते हैं वह पार्टी सदस्यों के उदाहरणात्मक अगुआ भूमिका साथ ही आगे की कतारों की लड़ाकू टुकड़ियों के रूप में पार्टी शाखाओं की भूमिका से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्टी के प्राथमिक संगठनों को पार्टी समूहों द्वारा मुहैया कराई गई महत्वपूर्ण कड़ी को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ने में संकल्पबद्ध होना चाहिए और उनकी जुझारू भूमिका को पूरी तरह सक्रिय बनाना चाहिए। पार्टी समूहों को इस बात को सचेतन तौर पर निश्चित कर लेना चाहिए कि उनके सदस्य मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा, पार्टी निर्माण पर अध्यक्ष माओ की लाइन, पार्टी संविधान, साथ ही साथ संशोधनवाद का खण्डन करने वाले दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं। उन्हें पार्टी की बुनियादी राजनीतिक लाइन और सिद्धान्तों को थामना चाहिए, अपने सदस्यों की वर्ग संघर्ष और दो लाइनों के संघर्ष की चेतना को ऊपर उठाना चाहिए, साथ ही साथ असली और नकली मार्क्सवाद में भेद करने की उनकी क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए, और वर्ग शत्रु के विरुद्ध संघर्ष में पार्टी सदस्यों और क्रान्तिकारी जनसमुदायों की अगुआई करनी चाहिए। इन समूहों को नये सदस्यों को भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षित और परीक्षित करने के अच्छे काम को भी अंजाम देना चाहिए और स्थिति के बारे में पार्टी शाखा को सूचित करना चाहिए। पार्टी समूहों को पार्टी शाखा के निर्णयों को लागू करने, शाखा द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने, पार्टी सदस्यों और जन समुदायों की सैद्धान्तिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने और उनकी चाहतों को प्रतिबिम्बित करने के कामों को भी करना चाहिए। उन्हें अक्सर आलोचना और आत्मालोचना की पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी के ऐसे सदस्यों को, जो कैडर भी हैं और नेतृत्व की जिम्मेदारियों को भी उठाते हैं, किसी पार्टी समूह में शामिल हो जाना चाहिए और साधारण सदस्यों की ही तरह इसकी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।

हमें अपने आपको सैद्धान्तिक रूप से क्रान्तिकारी बनाना चाहिए ताकि पार्टी शाखाएं वस्तुतः "दस्ते" बन जायें ओर पार्टी के प्राथमिक संगठनों की नेतृत्वकारी भूमिका को पूर्णतः सक्रिय करें। अगली कतारों की लड़ाकू टुकड़ी के रूप में पार्टी के जन संगठनों की भूमिका को पूर्णतः सक्रियता में लाने में कुंजीभूत विन्दु एक क्रान्तिकारी नेतृत्वकारी निकाय को स्थापित करना है जिसका जन समुदायों के साथ नजदीकी रिश्ता है और जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पार्टी के प्राथमिक संगठनों का नेतृत्व दृढ़तापूर्वक मार्क्सवादी क्रान्तिकारियों, मजदूरों, गरीब और मध्यम किसानों और मेहनतकश जनता के दूसरे नुमाइंदों के हाथ में है। पार्टी के प्राथमिक संगठनों को सामूहिक नेतृत्व को कामों और जिम्मेदारियों के बंटवारे से जोड़ने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। जहां तक बेहद अहम मामलों का सवाल है, उन पर शाखा कमेटी (या पार्टी कमेटी) द्वारा निर्णय लिये जाने और लागू किये जाने से पहले सामूहिक रूप से विचार-विमर्श हो जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों की राय ली जानी चाहिए, किसी एक अकेले व्यक्ति की नहीं। प्राथमिक संगठनों की कमेटियों को नियमित रूप से संगठन के जनवादी जीवन को विकसित करना चाहिए और परस्पर आलोचना और आत्मालोचना में लगना चाहिए ताकि वह केन्द्रीकृत नेतृत्व मजबूत हो सके जिन्हें वे क्रान्तिकारी कमेटियों, लेबर यूनियनों, गरीब और निम्न मध्यम किसानों की सभाओं, महिलाओं के संघों, कम्युनिस्ट यूथ लीग, रेड गार्ड ओर लिटिल रेड गार्ड और क्रान्तिकारी जन समुदायों के दूसरे संगठनों पर लागू करते हैं। प्राथमिक संगठनों के नेतृत्वकारी निकायों को सचेतन रूप से मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्लासिक रचनाओं और अध्यक्ष माओ की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए, तीन महान क्रान्तिकारी आंदोलनों की अगली कतार में रहना चाहिए, खास तौर पर वर्ग संघर्ष, उत्पादन और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए संघर्ष, अपने विश्व दृष्टिकोण को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमेशा कामगार लोगों के अच्छे गुणों को कायम रखना चाहिए ताकि नौकरशाही से बचा जा सके और उसे हराया जा सके, संशोधनवाद से बचा जा सके और हमेशा अपनी क्रान्तिकारी नौजवानी को कायम रखा जा सके। जब पार्टी शाखाओं को "दस्ता" बन जाने की हद तक क्रान्तिकारी बनाया जा चुका हो, सम्पूर्ण पार्टी के कामों को जबर्दस्त संवेग मिलेगा ओर पार्टी के प्राथमिक संगठन अगली कतारों की लड़ाकू टुकड़ियों की अपनी भूमिका को पूरी तरह निभा पाने के काबिल होंगे। (क्रमशः)

जिन मामलों को आप खुद नहीं समझते या नहीं जानते, उनके बारे में अपने मातहत काम करने वालों से जानकारी हासिल करो, तथा गहराई से विचार किये बिना अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रकट न करो।... जो काम हम नहीं जानते उसके बारे में हमें यह दिखावा हरगिज नहीं करना चाहिए कि हम उसे जानते हैं, हमें "अपने मातहत काम करने वाले लोगों से सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए" तथा हमें निचली इकाइयों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की राय को गौर से सुनना चाहिए। शिक्षक बनने से पहले एक शिष्य बनो; आदेश जारी करने से पहले निचली इकाइयों के कार्यकर्ताओं से सीखो। जो कुछ निचली इकाइयों के कार्यकर्ता कहें वह सही भी हो सकता है और नहीं भी; उसे सुनने के बाद हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। हमें सही राय को मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए...। निचली इकाइयों के गलत विचारों को भी सुनना चाहिए; उन्हें बिल्कुल न सुनना गलत होगा। लेकिन इस प्रकार के विचारों पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी आलोचना करनी चाहिए।

–माओ त्से-तुङ (पार्टी-कमेटियों के काम करने के तरीके)

"पियानो बजाना" सीखो। पियानो बजाते समय दस की दस उंगलियां हिलती रहती हैं, केवल कुछ ही उंगलियों को हिलाने और बाकी को न हिलाने से काम नहीं चलता। लेकिन अगर दस की दस उंगलियों को एक साथ दबाया गया, तो मधुर ध्वनि नहीं निकलेगी। अच्छा संगीत प्रस्तुत करने के लिए दसों उंगलियों को बड़े लयात्मक ढंग से और एक दूसरे से तालमेल कायम करते हुए हिलाना चाहिए। एक पार्टी-कमेटी को अपने केन्द्रीय कार्य को दृढ़ता से चलाना चाहिए, तथा साथ ही केन्द्रीय कार्य के इर्द-गिर्द उसे अपने अन्य कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इस समय हम बहुत से क्षेत्रों के कार्यों का संचालन करते हैं; हमें सभी इलाकों, सशस्त्र यूनिटों और विभागों के कार्य की देखभाल करनी चाहिए, तथा अपना समूचा ध्यान बाकी सब मसलों को छोड़कर केवल चन्द मसलों पर ही केन्द्रित नहीं कर देना चाहिए। जहां कहीं भी समस्या मौजूद हो, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, तथा कार्य करने के इस तरीके में माहिर बन जाना चाहिए कुछ लोग पियानों अच्छी तरह बजाते हैं और कुछ लोग बुरी तरह तथा उनके द्वारा पैदा की जाने वाली धुनों में भी बहुत फर्क होता है। पार्टी-कमेटियों के सदस्यों को "पियानो बजाना" अच्छी तरह सीख लेना चाहिए।

–माओ त्से-तुङ (पार्टी-कमेटियों के काम करने के तरीके)

मजदूर आंदोलन के क्रान्तिकारीकरण की कोशिशें तेज करो!

एक तरफ तो सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के गठन और निर्माण की बात जोर-शोर से दुहरायी जाती है लेकिन सर्वहारा वर्ग के बीच से क्रांतिकारी भर्ती के काम पर कोई जोर नहीं दिखायी देता है।

(पेज 1 से आगे)

दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया के साथ ही देश के भीतर भी हम जबर्दस्त जनउभारों के गवाह होने जा रहे हैं। यह संभावना कोई सुदूर भविष्य की बात भी नहीं है। पिछले छप्पन सालों में पूंजीवादी विकास चाहे जितना कछुआ चाल से ही हो रहा हो लेकिन सुदूर गांव-देहात की जिंदगी को भी पूंजी के काले डैनों ने ढंक लिया है। गांवों की गरीब-मध्यम किसान आबादी के अपनी जगह-जमीन से उजड़ने की रफ्तार पिछले दस सालों में काफी तेज हो गयी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक नये-पुराने औद्योगिक इलाकों में उजरती मजदूरों का महासागर हिलोरें ले रहा है। अगर गांव-शहर की सर्वहारा-अर्द्धसर्वहारा आबादी की जनसंख्या का एक मोटा आंकड़ा भी लगाया जाये, तो यह संख्या कुल आबादी के आधे यानी पचास फीसदी तक पहुंच रही है। केवल शुद्ध खेतिहर और औद्योगिक सर्वहारा की बात करें, तो भी यह आंकड़ा 30-35 फीसदी को छू रहा है। देश में नयी आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद यही आबादी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। हमारे समाज का यही वह वर्ग है जो क्रांतिकारी बदलावों की लहर में अगली कतारों में चलने वाला है। आक्रोश का बारूद भी इसी आबादी के बीच सबसे घना इकट्ठा होता जा रहा है। तबाह-बर्बाद मेहनतकश किसान आबादी और परेशानहाल शहरी मध्यवर्ग इस सर्वहारा- अर्द्धसर्वहारा क्रांतिकारी आबादी के पीछे-पीछे ही चलेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में समाज के इस सर्वाधिक क्रांतिकारी और विकासमान वर्ग से हरावल की कतारों में कितनी भर्तियां हुई हैं? एक तरफ तो सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के गठन और निर्माण की बात जोर-शोर से दुहरायी जाती है लेकिन सर्वहारा वर्ग के बीच से क्रांतिकारी भर्ती के काम पर कोई जोर नहीं दिखायी देता है।

ऐसा लगता है कि आज देश में मौजूद अधिकांश हरावल शक्तियों की हालात की समझ से पकड़ पूरी तरह छूट चुकी है। कठमुल्लावाद और अतीत की महान क्रांतियों की नकल उतारने की प्रवृत्ति इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि नये हालात को नयी नज़र से देखने की क्षमता पूरी तरह गंवायी जा चुकी है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये शक्तियां एक सच्ची सर्वहारा पार्टी के निर्माण व गठन की क्षमता खो चुकी हैं। जड़ता इतनी गहरी है कि उसे तोड़ने के लिए जिस जबर्दस्त संवेग और नये क्रांतिकारी रक्तसंचार की जरूरत होती है उसके संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। इन हालात में आज मौजूद तमाम पुरानी संरचनाओं को मिलाकर कोई नयी संरचना बन भी जाये तो वह सर्वहारा क्रांति के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में कितनी कारगर होगी? इस पर आज सिर्फ संदेह ही व्यक्त किया जा सकता है।

आज के इस नये दौर में सर्वहारा वर्ग के बीच नयी क्रांतिकारी भरती का काम पार्टी निर्माण का एक बुनियादी काम है। यह सफलतापूर्वक तभी अंजाम दिया जा सकता है जब सर्वहारा आबादी के बीच सही क्रांतिकारी जनदिशा लागू की जाये। लेकिन आज दिख यह रहा है कि क्रांतिकारी जनदिशा लागू करने के नाम पर अर्थवाद की लाइन लागू हो रही है। अमल में जो हो रहा है उससे यही सोच उभरकर सामने आती है कि अगर मजदूरों की आर्थिक लड़ाइयों को जुझारू ढंग से या किसी भी किस्म का समझौता किये बिना लड़ते रहा जाये तो इससे मजदूरों की राजनीतिक चेतना अपने आप उन्नत स्तर पर पहुंच जायेगी। इसी रास्ते अपने आप पार्टी भर्ती होती रहेगी। ऐसा लगता है कि अर्थवाद के खिलाफ लेनिन ने जो लड़ाइयां लड़ीं, उसके ऐतिहासिक सबक जरा भी लागू नहीं किये जा रहे हैं। व्यापक मजदूर आबादी के बीच राजनीतिक प्रचार-प्रसार के नये-नये रचनात्मक रूपों को गढ़ने की ओर भुला दिये गये मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक मिशन को मजदूर वर्ग की स्मृतियों में जिंदा करने की दिशा में सचेतन कोशिशें दिखायी नहीं देतीं, जबकि अर्थवादियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लेनिन की सबसे कीमती शिक्षा यही थी।

कुछ लोग इस प्रवृत्ति को 'सशस्त्र अर्थवाद' का नाम दे रहे हैं। हमारी राय है कि क्रांतिकारी जनदिशा को लागू करने के नाम पर वामपंथी दुस्साहसवाद और अर्थवाद की एक बेस्वाद खिचड़ी पकायी जा रही है। जबकि जरूरत इस बात की है कि ट्रेड यूनियन राजनीति को मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी राजनीति और क्रांतिकारी मजदूर वर्ग के आम लक्ष्यों यानी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर पूरे समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण के लक्ष्यों के मातहत लाया जाये। इसके बिना अर्थवाद के दलदल में धंसे मजदूर आंदोलन को क्रांतिकारी धार और दिशा देने का काम अंजाम नहीं दिया जा सकता।

भूमंडलीकरण के मौजूदा दौर में पैदा हुए नये हालात ने ट्रेड यूनियन राजनीति की सीमाओं को पहले के दौरों के मुकाबले ज्यादा तीखेपन के साथ उजागर किया है। अपने मुनाफे की दर को लगातार बढ़ाते जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी ने जो नयी रणनीति अख्तियार की है उसने बचे-खुचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की कमर तोड़कर रख दी है। असेंबली लाइन को देश के भीतर ही नहीं दुनिया के कोने- कोने में बिखरा देना, परमानेंट मजदूरों से काम कराने के बजाय अधिकांश काम कैजुअल व ठेका मजदूरों से करवाना—ये अंतरराष्ट्रीय पूंजी की नयी रणनीतियां हैं। नतीजतन परंपरागत अर्थों में जिसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है, वही टूट-बिखर रहा है। यही कारण है कि संगठित क्षेत्र ट्रेड यूनियनवाद (जिसे शॉप फ्लोर ट्रेड यूनियनिज्म भी कहा जाता है) भी बेमानी होता जा रहा है। एक कारखाने के मालिक से मजदूरों की आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष संगठित करना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। यानी एक अर्थ में पुराने किस्म के अर्थवाद की जमीन भी खिसक रही है। इस नयी सच्चाई के सामने आने से पुरानी ट्रेड यूनियन राजनीति औंधे मुंह गिर पड़ी है।

लेकिन यह ट्रेड यूनियन राजनीति की सीमा है। जमीनी सच्चाइयों में यह बदलाव क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए कुछ फौरी चुनौतियां-कठिनाइयां लेकर जरूर आया है, लेकिन इस बदलाव के वे पहलू हमारी आंखों से नहीं ओझल होने चाहिए जो मजदूर आंदोलन को अर्थवाद से बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। यह सही है कि असेंबली लाइन बिखरा देने को मजदूर वर्ग आज अपनी ताकत को बिखर जाने के रूप में ले रहा है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग का भौतिक विखंडन उसके आत्मिक विखंडन को जन्म दे रहा है। पूंजी के नये हमलों के खिलाफ वह खुद को बेबस और अकेला समझकर निराशा की मनःस्थिति में जी रहा है। किसी एक कारखाने में बंधे न होने के चलते ठेका और कैजुअल मजदूरों को संगठित करने की व्यावहारिक चुनौतियां भी बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। लेकिन क्या इस पहलू पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए कि आज मजदूर वर्ग एक वर्ग के रूप में समूचे मालिक वर्ग, उसकी सरकार और समूची राजसत्ता के सामने खुद को खड़ा महसूस कर रहा है। आज जमीनी हालात मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को ऊंचा उठाने के नजरिये से ज्यादा अनुकूल हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्षों की दूरियां सिमट गयी हैं। सच्चाई के इस पहलू पर अगर हम गौर करें तो हम आज के मजदूर आंदोलन के बारे में कुछ जरूरी नतीजे निकाल सकते हैं।

मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार की इस अनुकूल परिस्थिति का फायदा भी हम तभी उठा सकते हैं जब ट्रेडयूनियनवाद या अर्थवाद की बीमारी के छोटे से छोटे कीटाणुओं से हम पूरी तरह मुक्त हों। नहीं तो नये हालात में भी हम आर्थिक लड़ाइयों के कुछ नये दायरे तलाश कर कदमताल करते रहेंगे। राजनीतिक प्रचार की अनुकूलता का अर्थ यह कत्तई नहीं है कि प्रचिलित घिसे-पिटे तरीकों से हम आसानी के साथ मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं और आसानी के साथ मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने की ओर बढ़ सकते हैं। मजदूर वर्ग के भीतर हताशा-निराशा जितनी गहरी है, अर्थवाद की बीमारी ने जितने गहरे तक अपना असर डाला है और पूंजीवादी सत्ता के पास मजदूर वर्ग के मानसिक-सांस्कृतिक अनुकूलन के जितने कारगर साधन और नयी क्षमताएं हासिल हुई हैं उसे देखते हुए आज मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षण का काम भी अधिक चुनौतीभरा हो गया है। आज यह लेनिन के समय से भी कई-कई गुना अधिक जटिल और चुनौती भरा हो चुका है। यही नहीं, यह कई परतों वाला और लंबे समय तक जारी रहने वाला बन गया है। यह मजदूर वर्ग के हरावलों से न केवल सूझबूझ और धीरज की मांग करता है बल्कि व्यापक मजदूर आबादी के साथ जीवंत रूप से जुड़ने की मांग करता है।

व्यापक मजदूर आबादी के भीतर हताशा-निराशा की मौजूदगी की बात तो समझ में आ सकती है क्योंकि क्रांति का विज्ञान उसका प्राधिकार नहीं बन सका है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आज के कठिन हालात में मजदूर वर्ग के हरावलों में भी गहराई तक हताशा-निराशा और हार की मानसिकता घर कर गयी है। इसका कारण सर्वहारा क्रांति के विज्ञान की वास्तविक समझ की कमी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के मजदूरों के क्रांतिकरी नेता माओ त्से-तुङ ने एक बार कहा था कि कठिनाइयां उपस्थित ही इसलिए होती हैं कि उन्हें जीता जाये। अगर मजदूर क्रांति के विज्ञान की हमारी पकड़ मजबूत है और सच्ची क्रांतिकारी स्पिरिट जिंदा हो तो मजदूर वर्ग के हरावल कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की राह निकाल ही लेते हैं। इतिहास ने बार-बार इसे सही साबित किया है। आज जरूरत न हो तो मिथ्या आशावाद में जीने की है और न ही निराश होने की। जरूरत है सच्चे क्रांतिकारी साहस के साथ धारा के खिलाफ खड़े होने की, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी विज्ञान मार्क्सवाद पर मजबूत पकड़ कायम कर ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण की, कड़ुवी सच्चाइयों को स्वीकार करने के वैज्ञानिक साहस की। केवल तभी हम मेहनत के लुटेरों के 'स्वर्ग पर धावा' बोलने की तैयारियां तेज कर सकते हैं। केवल तभी हमारा संकल्प सच्चा क्रांतिकारी संकल्प हो सकता है। आइये हम नये साल में मजदूर वर्ग की एक सही-सच्ची क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण एवं गठन और मजदूर आंदोलन के क्रांतिकारीकरण की कोशिशों को तेज करने का संकल्प लें।

क्रांतिकारी जनदिशा को लागू करने के नाम पर वामपंथी दुस्साहसवाद और अर्थवाद की एक बेस्वाद खिचड़ी पकायी जा रही है। जबकि जरूरत इस बात की है कि ट्रेड यूनियन राजनीति को मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी राजनीति और क्रांतिकारी मजदूर वर्ग के आम लक्ष्यों यानी राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर पूरे समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण के लक्ष्यों के मातहत लाया जाये।

आज आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्षों की दूरियां सिमट गयी हैं। सच्चाई के इस पहलू पर अगर हम गौर करें तो आज के मजदूर आंदोलन के बारे में कुछ जरूरी नतीजे निकाल सकते हैं।

नया वर्ष
नयी उम्मीदों
नयी तैयारियों
नयी शुरुआतों के नाम,
पराजय की घड़ी में भी
विजय के स्वप्नों के नाम,
लगातार लड़ते रहने की
जिद के नाम
संकल्पों के नाम
जीवन, संघर्ष और सृजन के नाम

नया वर्ष
युवा दिलों के नाम
ज़िन्दा कौमों के नाम,
साहसिक यात्राओं के नाम,
सक्रिय ज्ञान के नाम,
न्याय-युद्ध में भागीदारी की
तत्परता के नाम,
सच्चे प्यार के नाम,
मानवता के भविष्य में
उत्कट आस्था के नाम!

आज जरूरत न हो तो मिथ्या आशावाद में जीने की है और न ही निराश होने की। जरूरत है सच्चे क्रांतिकारी साहस के साथ धारा के खिलाफ खड़े होने की, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी विज्ञान मार्क्सवाद पर मजबूत पकड़ कायम कर ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण की, कड़ुवी सच्चाइयों को स्वीकार करने के वैज्ञानिक साहस की।

बकलमे-खुद

इस स्तम्भ के बारे में

इस स्तम्भ के अन्तर्गत हम जिन्दगी की जद्दोजहद में जूझ रहे मजदूरों और उनके बीच रहकर काम करने वाले मजदूर संगठनकर्ताओं- कार्यकर्ताओं की साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित करते हैं—कविताएं, कहानियां, डायरी के पन्ने, गद्यगीत आदि-आदि।

इस स्तम्भ की शुरुआत की एक कहानी है। 'बिगुल' के सभी प्रतिनिधियों-संवाददाताओं के अनुभव से यह जुड़ी हुई है। हमने पाया कि जो कुछ पढ़े-लिखे और उन्नत चेतना के मजदूर हैं, वे गोर्की की 'मां', उनकी आत्मकथात्मक उपन्यास-त्रयी और अन्य रचनाओं को तो बेहद दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, प्रेमचंद उन्हें बेहद पसन्द आते हैं, आस्त्रोव्स्की की 'अग्निदीक्षा' और पोलेवेई की 'असली इंसान' ही नहीं, कुछ तो बाल्जाक और चेर्निशेव्स्की को भी मगन होकर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हिन्दी के आज के सिरमौर वामपंथी कथाकारों की बहुचर्चित रचनाएं उन्हें पढ़ने को देते हैं तो वे बेमन से दो-चार पेज पलटकर धर देते हैं। पढ़कर सुनाते हैं तो उबासी या झपकी लेने लगते हैं। यदि उन सबकी राय को समेटकर थोड़े में कहा जाये, तो इसका कारण यह है कि ज्यादातर वामपंथी-प्रगतिशील लेखक आज अपनी रचनाओं में आम आदमी की जिन्दगी की, संघर्ष और आशा-निराशा की जो तस्वीर उपस्थित कर रहे हैं, वह आज की जिन्दगी की सच्चाइयों से कोसों दूर हैं। वह या तो ट्रेनों-बसों की खिड़कियों से देखे गये गांवों और मजदूर बस्तियों का चित्र है, या फिर अतीत की स्मृतियों के आधार पर रची गयी काल्पनिक तस्वीर। नयेपन के नाम पर जो कला का इन्द्रजाल रचा जा रहा है, वह भी आम जनता के लिए बेगाना है। कारण स्पष्ट है। दरअसल इन तथाकथित वामपंथियों का बड़ा हिस्सा "वामपंथी कुलीनों" का है। ये "कलाजगत के शरीफजादे" हैं जो प्रायः प्रोफेसर, अफसर या खाते-पीते मध्यवर्ग के ऐसे लोग हैं जो जनता की जिन्दगी को जानने-समझने के लिए हफ्ते-दस दिन की छुट्टियां भी उसके बीच जाकर बिताने का साहस नहीं रखते। ये अपने नेहनीड़ों के स्वामी सद्गृहस्थ लोग हैं। ये गरुड़ का स्वांग भरने वाली आंगन की मुर्गियां हैं। ये फर्जी वसीयतनामा पेश करके गोर्की, लू शुन, प्रेमचंद का वारिस होने का दम भरने वाले लोग हैं। समय आ रहा है जब क्रान्तिकारी लेखकों- कलाकारों की एकदम नई पीढ़ी जनता की जिन्दगी और संघर्षों के ट्रेनिंग-सेण्टरों से प्रशिक्षित होकर सामने आयेगी। इन कतारों में आम मजदूर भी होंगे। भारत का मजदूर वर्ग आज स्वयं अपना बुद्धिजीवी पैदा करने की स्थिति में आ चुका है। भारत का यह नया बुद्धिजीवी मजदूर या मजदूर बुद्धिजीवी सर्वहारा क्रान्ति की अगली-पिछली पांतों को नई मजबूती देगा। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम अपेक्षा करें कि भारतीय मजदूर वर्ग भी अपना इवान बाबुश्किन और मक्सिम गोर्की पैदा करेगा। 'बिगुल' की कोशिश होगी कि वह ऐसे नये मजदूर लेखकों का मंच बने और प्रशिक्षणशाला भी।

*इसी दिशा में, पहलकदमी जगाने वाली एक शुरुआती कोशिश के तौर पर इस स्तम्भ की शुरुआत की गयी है। मुमकिन है कि मजदूरों और मजदूरों के बीच काम करने वाले संगठनकर्ताओं की इन रचनाओं में कलात्मक अनगढ़ता और बचकानापन हो, पर इनमें जीवित यथार्थ की ताप और रोशनी के बारे में आश्वस्त हुआ जा सकता है। जिन्दगी की ये तस्वीरें सच्ची वामपंथी कहानी का कच्चा माल भी हो सकती हैं। और फिर यह भी एक सच है कि हर नयी शुरुआत अनगढ़-बचकानी ही होती है। लेकिन मंजे-मंजाये घिसे-पिटे लेखन से या काल्पनिक जीवन-चित्रण के उच्च कलात्मक रूप से भी ऐसा अनगढ़ लेखन बेहतर होता है जिसमें जीवन की वास्तविकता और ताजगी हो। हमारा यह अनुरोध है कि मजदूर साथी अपनी जिन्दगी की क्रूर-नंगी सच्चाइयों की तस्वीर पेश करने के लिए अब खुद कलम उठायें और ऐसी रचनाएं इस स्तम्भ के लिए भेजें। **साथ ही प्रकाशित रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया भी भेजें।***

इस अंक में हम एक मजदूर कार्यकर्ता जनार्दन की कहानी छाप रहे हैं।

—सम्पादक मण्डल

कहानी

बाकी सब ठीक नहीं है!

जनार्दन

प्यारे दोस्त,

तुम्हारा दुनियादारी के उपदेशों से लिथड़ा पत्र मुझे मिला। दो साल पहले जब मैंने जिंदगी की एक नई राह पकड़ी थी, तब तुमने मेरे रास्ते का दबी जुबान से विरोध किया था। आज का तुम्हारा पत्र बताता है कि तुम पर्याप्त दुनियादार हो चुके हो। बहरहाल, तुम्हारे द्वारा पत्र में मचाई गई मध्यवर्गीय चीख-पुकारों पर मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहता। इस वक्त एक घटना (हो सकता है तुम्हारे लिए वह बेहद मामूली हो) ने मेरे दिलो-दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपने घोंसले से बाहर की इस दुनिया को देखने के लिए।

झुग्गी बस्ती के जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, उन्हीं के घरों पर बारी-बारी से भोजन करने का मैंने तय किया है। ज्यादातर बच्चों के मां-बाप की यह स्थिति भी नहीं है कि वह फीस देकर पढ़ा सकें। बच्चे मेरे साथ हिल-मिल गये हैं। आज मैं अजित के घर रात का भोजन करने गया था। बारह साल के इस बच्चे के चेहरे की उदासी हमेशा ही मुझे परेशान करती थी।

मैं अजित के घर पहुंचा तो उसकी मां रोटी बना रही थी। खाना परोसकर वह वहीं बगल में दोनों घुटनों पर सिर टिकाये चूल्हे के पास बैठ गयी और बोलने लगी। उसकी आवाज ठंडी थी। वह लगातार बोलती रही। और मैं खाना खाते हुए चुपचाप सुन रहा था। वह कह रही थी, "मास्टर जी, आजकल मैं बहुत परेशानी में हूं। इसके पापा अभी जेल में हैं।" इस पर मैंने थोड़ा आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो उसने आगे कहा, "हां मास्टर जी, उनको नौ महीने हो गये जेल गये हुए। सेक्टर अट्ठावन में डायरी बनाने वाली एक फैक्ट्री में वह काम करते थे। अच्छा-भला काम कर रहे थे। एक दिन इनकी कंपनी में एक झाड़ू लगाने वाली बुढ़िया, शाम को जब झाड़ू लगाने आई, तो कंपनी में ही कुछ चट्टियां (बोरे) ओढ़कर सो गयी और नींद में ही मर गयी।

"सुबह ये जब कंपनी गये तो उस समय कोई आया नहीं था। ये खुद सफाई करने लगे। जब चट्टियों को हटाया तो उसी में बुढ़िया को मरा देख भौचक रह गये। इन्होंने तुरंत मालिक को फोन किया। मालिक ने आने से पहले पुलिस को भेज दिया। पुलिस इनको पकड़ कर ले गयी। बाद में मालिक हम लोगों को दिलासा देने लगा कि घबराओ नहीं, हम उनको छुड़ा लेंगे। उधर मालिक ने अंदर ही अंदर कागज-पत्तर बनवाकर इन पर हत्या का मुकदमा ठोंक दिया। मैंने दो बार केस डालने की कोशिश की लेकिन मालिक ने पैसे के दम पर खारिज करवा दिया। अब मामला इलाहाबाद चला गया है। हम क्या करें मास्टर जी? हम बरबाद हो गये। ये चार भाई थे। इनके जेल जाने से पहले ही जो इनसे बड़े थे वह बेरहम मालिक की फैक्ट्री में ही मर गये। उनको मास्टर जी कुछ नहीं हुआ था। बस थोड़ा सा बुखार था। उस दिन वो बिना खाना खाये फैक्ट्री चले गये। लंच भी नहीं ले गये थे। सोचा था कि जाकर किसी हल्के काम पर लग जाऊंगा और आज आठ ही घंटे काम करके आ जाऊंगा। आज ओवरटाइम नहीं करूंगा। वहां गये तो मालिक ने कागज के बड़े-बड़े बंडल उतारने को कह दिया। पता नहीं कहां गलती हुई, पूरा जोर नहीं लगा, कि क्या हुआ, पूरा बंडल इनके ऊपर से होता हुआ दुगुर गया। और उसी में वह दब कर मर गये।"

उसने कहना जारी रखा, "अब मास्टर जी हम लोग क्या करते। कुछ लोग कहने लगे कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लाश को घर ले जाओ—नहीं तो क्या जवाब दोगे इसकी घरवाली को। समाज में, बिरादरी में क्या मुंह दिखाओगे? लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि यहीं फूंको, फोटो-ओटो खिंचवाओ, अखबार में दे दो, लेकिन मास्टर जी हम क्या करते। अंत में लाश को घर ही ले जाना पड़ा। रातों-रात मोटर तय हुआ, हम सभी बच्चों समेत और तीनो भाई, सबके-सब घर चले गये। घर जाते समय मालिक ने बीस हजार रुपया थमा दिया। और कहा कि—लो काम-किरिया कर लेना और जुबान बंद रखना। बहुत कहने-सुनने पर आठ सौ रुपया पेंशन पर मालिक राजी हो गया। उस समय इसके पापा ने सोचा था कि उधर से आयेंगे तो केस करेंगे।"

उसने आगे बताया "घर जाकर लोगों ने उनका काम-किरिया किया। उसी समय धान की फसल बोने का समय आ गया था। खेत बनाकर रोपाई करना था। दोनों भाई मिलकर इसके पापा को रोक लिए। अब रोपाई के बाद निराई का काम आ गया। उधर खेती के काम में बहुत लेट हो गया। इधर मामला ठंडा पड़ गया। केस डालने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन इसके पापा ने केस डाल दिया। वह केस भी अब जाकर खुला है, जब इसके पापा जेल में हैं।"

इसके बाद वह कुछ देर के लिए चुप हो गयी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक लंबी सांस भरकर वह कराह उठी और बोली, "सुनने में आया है मास्टर जी कि इनके दोनों भाइयों ने पता नहीं डर के कारण या लालच वश गवाही दी है कि वह फैक्ट्री में बीमारी के कारण मरा था। क्योंकि वह लंबे समय से बीमार चल रहा था। मैं जब भी इसके पापा से मिलने जाती हूं, हमेशा यही कहते हैं घबराओ नहीं छूट जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस बात का धीर धरूं? हमेशा बच्चे कहते हैं, मम्मी यह बनाओ, मम्मी वह बनाओ, लेकिन इन सबों का मुंह रोकना पड़ता है। उनको छुड़ाने के चक्कर में तीस हजार से अधिक कर्जा हो गया है। उधर से जेठ जी तीन-तीन जवान बेटियों को छोड़ कर मरे हैं। बड़ी लड़की की शादी में कम से कम दो लाख लगा था। कैसे होगा यह सब? केवल मेरा बड़ा लड़का काम करता है। परदेस में 3-3 बच्चों को लेकर खर्चा चलाना मुश्किल है। रात-दिन चिंता लगी रहती है। हमेशा मैं काम के बारे में सोचती हूं। लेकिन वह कहते हैं कि जिंदगी भर बैठा कर खिलाया, अब तुम बाहर क्या निकलोगी? गांव पर तो कुछ भी हो जाय, नाक रगड़ कर अंदर ही मरो, लेकिन बाहर नहीं निकलना होता है। यहां तो परदेस है, साग-सब्जी लेने, पानी भरने बाहर निकल जाती हूं। मैं बार-बार कहती हूं कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, काम करने में क्या बुराई है? आखिर इस झुग्गी में सारी औरतें तो काम करती ही हैं। हम सवर्ण हैं तो क्या हुआ? यहां तो सब कमाते हैं चाहे बबुआन हों या नान्ह जात। लेकिन मेरी एक नहीं सुनते। अब तो झुग्गी भी टूटने वाली है, अब मैं कहां जाऊंगी?" उसका गला रुंध गया और आवाज अटक गयी। फिर खामोशी छा गयी।

मैंने किसी तरह खाना खाया। ये सब कुछ सुनकर मेरा दिल अवसाद से भर गया। अब समझ में आ रहा था कि अजित के चेहरे पर छाई रहने वाली मायूसी की वजह क्या है। हालांकि, आज वह बहुत खुश था, उसके मास्टर जी घर जो आये थे।

दोस्त,

कालेज के दिनों में तुम्हारे दिल में जो आग थी, उस पर पड़ चुकी राख को यह घटना कितना कुरेद पायेगी, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि ठंडे समय में इस आग को बचाये रखना बहुत जरूरी होता है। तुमने अपने पत्र में घर-परिवार की जो दुख-तकलीफ लिखी है, उस पर मैं क्या करूं? अभी तो मेरे सामने अजित का चेहरा है। और जाने कितने ही अजित इस समाज में हैं, जिनके चेहरे की उदासी हमारे किसी भी शोकगीत से ज्यादा मर्मांतक है।

'बाकी सब ठीक है', यह लिखने का अब कोई मतलब नहीं।

बाकी तुमसे मिलने पर।

तुम्हारा दोस्त,

अखिलेश

नोएडा

सामाजिक मंच अस्तित्व में आया।

ब्राजील के शहर पोर्तो अलेग्रे में वर्ष 2000 में विश्व सामाजिक मंच का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस मंच के गठन का प्रस्ताव फ्रांस सरकार के टुकड़ों पर पलने वाली संस्था 'अटैक' (ए.टी.टी.ए.सी.-एसोसिएशन फॉर द टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड फॉर असिस्टेंस टू सिटिजंस) नामक संस्था के बर्नार्ड काजेन ने किया था। इस प्रस्ताव को ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला दा मेला की वर्कर्स पार्टी और ब्राजील में काम करने वाली आठ नामधारी गैरसरकारी संस्थाओं ने हाथों-हाथ लिया और उन्होंने मार्च 2000 में पोर्तो अलेग्रे में सम्मेलन करना तय किया। बाद में यूरोप में काम कर रहे दर्जनों एन.जी.ओ. इससे जुड़ते चले गये।

डब्ल्यू.एस.एफ. के इस पहले आधिकारिक सम्मेलन में 10,000 लोग इकट्ठा हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस आधिकारिक सम्मेलनके समांतर पोर्तो अलेग्रे में ही एक और सम्मेलन हुआ जिसमें 50000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। इस सम्मेलन के भी मुख्य कर्ता-धर्ता किसिम-किसिम के एन.जी.ओ. ही थे, लेकिन सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल आम आबादी भूमंडलीकरण की लुटेरी नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने पहुंची थी। हालांकि, आधिकारिक सम्मेलन के आयोजकों ने इस समांतर सम्मेलन को नजरअंदाज किया और अपना एक 18 सूत्री घोषणपत्र जारी किया।

सम्मेलन के लिए पोर्तो अलेग्रे का चुनाव भी अनायास नहीं था। यह शहर उस राज्य की राजधानी है, जहां उस समय ब्राजील की वर्कर्स पार्टी की अगुवाई में एक मिली-जुली सरकार कायम थी। पार्टी के मुखिया लूला आगे संसदीय चुनावों में जीतकर ब्राजील के राष्ट्रपति बने। इस राज्य में लूला की पार्टी के सहयोग-समर्थन से पूंजीवादी जनतंत्र को मजबूत बनाने वाले एन.जी.ओ मार्का सुधार के काम जैसे 'भागीदारी जनतंत्र', 'जमीनी जनतंत्र' जैसे लुभावने जुमलों की आड़ में गरीब और वंचित आबादी को सत्ता में भागीदारी दिलाने की कवायदें बड़े पैमाने पर चल रही हैं। कहा जा सकता है कि पोर्तो अलेग्रे दुनिया भर के एन.जी.ओ. का मक्का बन गया है।

डब्ल्यू.एस.एफ. की ब्राजीली आयोजन समिति इसके अंतरराष्ट्रीय सचिवालय का काम करती है, जिसमें 'अटैक', लूला की वर्कर्स पार्टी और उसके यूरोपीय बिरादरों का ही दबदबा है। मंच की अंतरराष्ट्रीय परिषद 80 संगठनों को मिलाकर बनी है जिसमें 'अटैक', 'जेनोवा सोशल फोरम', त्रात्सकीपंथी चौथे इंटरनेशनल का एक धड़ा, 'अमेरिकन काउंसिल आफ सोशल साइंसेज', सामिर अमीन का 'वर्ल्ड फोरम ऑफ आल्टरनेटिव्स' और इटली के कम्युनिस्ट रिफाउंडेशन समेत तरह-तरह के एनजीओ की भरमार है।

डब्ल्यू.एस.एफ. का दूसरा और तीसरा सम्मेलन भी पोर्तो अलेग्रे में ही हुआ। जनवरी 2002 में आयोजित दूसरे सम्मेलन में कई यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे। फ्रांस के राष्ट्रपति जॉक शिराँक ने प्रधानमंत्री लियोनेल जॉस्पें सहित छह मंत्रियों और पेरिस के मेयर को सम्मेलन में भेजा। इसके अलावा बेल्जियम के प्रधानमंत्री और पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने अपने देश में मजदूर वर्ग के भारी विरोध को अनदेखा कर धड़ल्ले से भूमंडलीकरण की नीतियां लागू की थीं, भी इस सम्मेलन में पहुंचे हुए थे।

डब्ल्यू.एस.एफ. बनने की यह कहानी और सम्मेलनों में यूरोपीय साम्राज्यवादी लुटेरों के राजनीतिक नुमाइंदों की भागीदारी उसके भूमंडलीकरण विरोधी चेहरे को अपने आप नोंचकर फेंक देती है। लेकिन भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे इसके लिए उसके घोषणापत्र में किये गये राजनीतिक दावों और उसे रकम मुहैया कराने वालों के चेहरों को देख लेना भी जरूरी है।

डब्ल्यू.एस.एफ. का राजनीतिक छद्म

डब्ल्यू.एस.एफ. का घोषणापत्र यह दावा करता है कि यह मंच साम्राज्यवाद के सभी रूपों और पूंजी के विश्वव्यापी दबदबे तथा नवउदारवाद (या भूमंडलीकरण की नीतियों) का विरोध करने वाले 'सभ्य समाज' के विभिन्न समूहों एवं आंदोलनों को कारगर कार्रवाई के लिये एक मंच पर लाने की कोशिश है। इसके लिये यह मंच करेगा क्या? वस्तुतः कुछ नहीं! क्योंकि यह मंच केवल इन समूहों और आंदोलनों के बीच 'जनवादी ढंग से विचारों के आदान-प्रदान' और 'गहन चिंतन-मनन' का खुला मंच है। यानी यह कोरी गप्पबाजी का अड्डा है। मंच के तथाकथित सभ्य समाज की अवधारणा में ही वह असली झोल है, जिसके तहत दुनिया की जनता के जालिम लुटेरे हुक्मरान भी आते हैं और इनके शोषण व जोरो-जुल्म का विरोध करने वाली जनता भी। मंच जालिमों के दरबार में मजलूमों की नालिश कराने का खुला मौका देना चाहता है। गौरतलब है कि 'सभ्य समाज' की यह शब्दावली आजकल एन.जी.ओ. वालों ही नहीं बल्कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रोकोष और संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी लुटेरी संस्थाओं के दस्तावेजों में खूब चलन में है।

लेकिन इस खुले मंच का खुलापन उस समय बेनकाब हो जाता है जब यह क्रांतिकारी जनांदोलनों एवं समूहों के लिए इस मंच के दरवाजे पूरी तरह बंद कर देने का ऐलान अपने घोषणापत्र में करता है। **"मंच में न तो पार्टियों और न ही सशस्त्र कार्रवाई करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। (मंच के) घोषणापत्र को स्वीकार करने वाले सरकार के नेताओं और विधायिकाओं के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का आमंत्रण दिया जा सकता है।"**

मंच के घोषणापत्र का नौवां नुक्ता ठीक-ठीक यही बात करता है। साफ है कि यह खुला मंच दुनिया के लुटेरे शासक वर्गों के नुमाइंदों, मजदूर वर्ग से गद्दारी कर पूंजीवाद-साम्राज्यवाद की चाकरी में जुटी सी.पी.आई.-सी.पी.एम. जैसी सामाजिक जनवादी पार्टियों (चुनावी वामपंथी पार्टियों) और तरह-तरह के एन.जी.ओ. के लिए तो खुला है लेकिन क्रांतिकारी पार्टियों और उनके सैन्य विभागों के लिए इसके दरवाजे पूरी तरह बंद हैं।

मंच किस तरह कोरी गप्पबाजी का अड्डा है इसे भी स्वयं घोषणापत्र ही जाहिर कर देता है। इसमें एक जगह कहा गया है कि मंच ऐसी संस्था नहीं है, जो उसमें शामिल सभी संगठनों और लोगों की ओर से कोई साझा निर्णय लेगी। यानि व्यवहारतः वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा सिर्फ "गहन चिंतन-मनन" के लिए जगह मुहैया करायेगा। यानी मंच के कर्ता-धर्ता पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा मानते हैं जिसे केवल समझा-बुझाकर व चिरौरी-मिन्नत कर ठीक रास्ते पर लाया जा सकता है। मंच पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना 'सभ्य समाज' के खिलाफ मानता है। घोषणापत्र घुमा-फिराकर मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाज के विकास की मार्क्सवादी अवधारणा और समाजवाद का विरोध करते हुए हर तरह की हिंसा के खिलाफ अहिंसा के उपदेशक की मुद्रा अख्तियार कर 'मानवाधिकारों के सम्मान', 'वास्तविक जनवाद' और 'भागीदारी जनवाद' को लागू करने की चर्चा करने लगता है।

कुल मिलाकर नवउदारवादी (भूमंडलीकरण) की नीतियों और साम्राज्यवाद के सभी रूपों का विरोध करने की जुगाली करते हुए डब्ल्यू.एस.एफ. पूंजीवाद-साम्राज्यवादी विरोधी जनसंघर्षों की आंच पर पानी के छींटे डालने की शातिराना कारगुजारियों में लिप्त है। यह नयी दुनिया का जो नक्शा दुनिया के मेहनतकश अवाम के सामने पेश करने का दावा करता है वह और कुछ नहीं मुनाफे की अंधी लूट, युद्धों की तबाही और अनगिनत किस्म के अन्याय-अत्याचार में डूबी यही पूंजीवादी-साम्राज्यवादी दुनिया है। डब्ल्यू.एस.एफ के कर्ता-धर्ता इस व्यवस्था का खात्मा नहीं चाहते, बस उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, जिससे इसके कुरूप चेहरे को थोड़ा सा चमकाया जा सके। ये भूमंडलीकरण के दानवी चेहरे पर एक मानवीय मुखौटा पहनाना चाहते हैं, जिससे दुनिया की जनता में पनप रहा आक्रोश ठंडा पड़ जाये और विश्व पूंजीवाद उसके कोप-कहर से महफूज रहे।

डब्ल्यू.एस.एफ. को मोटी रकम देने वालों का असली चेहरा

डब्ल्यू.एस.एफ. के भीतर आधे से अधिक संगठन साम्राज्यवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले एन.जी.ओ. हैं। **फोर्ड फाउंडेशन** ने वर्ष 2001 और 2002 में ब्राजील में सक्रिय एन.जी.ओ. के एसोसिएशन को 3,28000 डालर की रकम बांटी। इसी तरह **आक्सफैम, हेनरिक बोल फाउंडेशन, आई.सी.सी.ओ.** (इंटर चर्च कोआर्डिनेशन कमेटी फॉर डेवलेपमेंट प्रोजक्ट) और **'अटैक'** जैसे अन्य एन.जी.ओ. मगरमच्छों ने डब्ल्यू.एस.एफ. को भारी रकमें मुहैया करायीं।

'आक्सफेम' (ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमीन रिलीफ) का गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अकाल राहत पहुंचाने के नाम पर हुआ था। 1960 और 1970 के दशक में दुनिया के कई देशों में इसका तेजी से फैलाव हुआ और आज लगभग सभी देशों में इसका जाल फैल चुका है। यह दुनिया में "गरीबी और सामाजिक अन्याय और असमानताओं के बुनियादी कारणों" को दूर करने के नाम पर तरह-तरह के "सुधार" कार्यों का जाल रचते हुए और कई दूसरे एन.जी.ओ के प्रोजेक्टों को रकमें बांटते हुए विश्व पूंजीवाद की सेवा में मुस्तैदी से जुटी है।

इसी तरह **हेनरिक बोल फाउंडेशन** ने सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, पारिस्थितिकी, टिकाऊ विकास आदि के नाम पर भी समाज सेवा का जाल बिछा रखा है। यह जर्मनी की मौजूदा सरकार में शामिल ग्रीन पार्टी से जुड़ी है, दुनिया के कई देशों में इसके दफ्तर और नेटवर्क हैं और यह कई इंस्टीट्यूट भी चलाती है। फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूट इसी का अंग है।

आई.सी.सी.ओ. भी डब्ल्यू.एस.एफ की एक भागीदार है जो एक प्रोटेस्टेंट एन.जी.ओ. है और इसे लगभग पूरी रकम हालैंड सरकार से मिलती है।

'अटैक' का गठन भी फ्रांस के एक नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर हुआ था। टोबिन "मुक्त व्यापार" के जोशीले समर्थक हैं। टोबिन ने वित्त के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर 0.05-1.04 प्रतिशत तक टैक्स लगाने की नसीहत दी थी। मकसद यह बताया गया था कि इससे जो धनराशि वसूली जायेगी उसका इस्तेमाल "विकास", व "गरीबी से लड़ने" में किया जायेगा। इस टैक्स को टोबिन टैक्स का नाम दिया गया। 'अटैक' इस टोबिन टैक्स के बारे में इस ढंग से प्रचार करता है जैसे इसके लागू होने से पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूटतंत्र को नुकसान पहुंचाये बिना गरीबी उड़नछू हो जायेगी और दुनिया विकास की डगर पर सरपट दौड़ चलेगी। फ्रांस की सरकार 'अटैक' को भारी मात्रा में धन मुहैया कराती है। फ्रांस के ही एक अखबार 'ल मोद' के अनुसार विश्व सामाजिक मंच के पहले सम्मेलन का आयोजन करने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने 80,000 यूरो की रकम दी थी।

डब्ल्यू.एस.एफ. में सामाजिक जनवादियों की भूमिका

साम्राज्यवादियों के धन से चलने वाले फाउंडेशन और साम्राज्यवादियों के ही टुकड़ों पर पलने वाले एन.जी.ओ. के अलावा दुनिया भर में मजदूरों की लड़ाइयों से गद्दारी कर पूंजीवाद की चाकरी करने में जुटी हुई सामाजिक जनवादी पार्टियां डब्ल्यू.एस.एफ. की मुख्य कर्ता-धर्ता हैं। ये सभी पार्टियां—चाहे भारत में सी.पी.आई.-सी.पी.एम. जैसी पार्टियां हों या ब्राजील की वर्कर्स पार्टी—भूमंडलीकरण की नीतियों को जोर-शोर से लागू कर रही हैं। ये सभी भूमंडलीकरण की नीतियों के नुकसानदेह प्रभावों के विरोध की जुगाली करते हुए भूमंडलीकरण के राक्षस पर मानवीय चेहरा चस्पां करने की कवायदों में जुटी हुई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला तो पूंजीपति लुटेरों के वैश्विक आर्थिक मंच और विश्व सामाजिक मंच के बीच पुल बनाने की जोर-शोर से वकालत करते हैं। भूमंडलीकरण विरोध के चैंपियन बने हुए लूला जनवरी 2003 के विश्व सामाजिक मंच के सम्मेलन से सीधे उठकर विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में साम्राज्यवादी मगरमच्छों से 'संरक्षणवाद' से बाज आने और 'मुक्त व्यापार' को बढ़ाने की आरजू करने जा पहुंचे थे।

भारत में सी.पी.आई और सी.पी.एम. पिछले साल हैदराबाद में सोशल फोरम के प्रमुख आयोजकों में थे और मुंबई के आयोजन में भी इनकी प्रमुख भूमिका है। हैदराबाद के तमाशे में आठ करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इस बार मुंबई के महातमाशे में यह आंकड़ा अरबों तक पहुंचने की उम्मीद है।

यूरोपीय साम्राज्यावदियों की डब्ल्यू.एस.एफ. में भागीदारी का अर्थ

मेहनतकश जनता की दुनिया भर में जारी लूट में अपने हिस्से के लिए सभी साम्राज्यवादी लुटेरों के बीच आपस में गलाकाटू होड़ मची हुई है। जब तक साम्राज्यवाद कायम रहेगा तब तक यह खत्म नहीं हो सकती। यूरोपीय साम्राज्यवादी विश्व सामाजिक मंच का इस्तेमाल अमेरिकी लुटेरों के साथ अपनी होड़ के मद्देनजर कुशलता से कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों के साथ एक मुसीबत यह भी है उनके देशों का मेहनतकश अवाम भूमंडलीकरण की नीतियों के खिलाफ आसानी से घुटने नहीं टेक रहा है। इसका कारण यूरोपीय मजदूर आंदोलन का पिछला शानदार इतिहास है। इसलिए यूरोपीय साम्राज्यवादी ऐसे मंचों पर उपस्थित होकर 'भूमंडलीकरण विरोधियों' के साथ खड़ा होकर अपने देशों में मेहनतकश अवाम के गुस्से की आग को थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं। साथ ही वे कुशलता के साथ भूमंडलीकरण विरोध को अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध का पर्यायवाची बनाकर जनसंघर्ष की धारा को भटकाने में भी लगे हुए हैं।

साम्राज्यवाद को सुधारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ तबाह किया जा सकता है

विश्व सामाजिक मंच ने साम्राज्यवाद विरोध का जो प्रपंच रचा है, उसे मेहनतकश अवाम को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। साम्राज्यवाद की समूची व्यवस्था को तबाह किये बिना एक नयी व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। जब तक यह साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम रहेगी—मानवता को भूख, बेकारी, लुटेरे युद्धों, अन्याय-उत्पीड़न और पूंजीवाद की विभीषिकाओं से नहीं बचाया जा सकता। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में किसी किस्म के सुधार की गुंजाइश या 'मानवीय चेहरे' वाले भूमंडलीकरण की बात करना छलावा है। विश्व स्तर पर समाजवादी व्यवस्था ही साम्राज्यवाद-पूंजीवाद का विकल्प हो सकती है और केवल दुनिया के मेहनतकश अवाम के क्रांतिकारी संघर्षों द्वारा इसे उखाड़ फेंकने के बाद ही नई व्यवस्था कायम की जा सकती है।

डब्ल्यू.एस.एफ. को बेनकाब करो

आज दुनियाभर में चल रहे पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्षों को गुमराह होने से बचाने के लिए यह एक जरूरी शर्त है कि

(पेज 11 पर जारी)

भिखमंगे आये !

मनबहकी लाल

●

भिखमंगे आये
नवयुग का मसीहा बनकर,
लोगों को अज्ञान, अशिक्षा और निर्धनता
से मुक्ति दिलाने।
अद्भुत वक्तृता, लेखन-कौशल और
सांगठनिक क्षमता से लैस
स्वस्थ-सुदर्शन-सुसंस्कृत भिखमंगे आये
हमारी बस्ती में।
एशिया-अफ्रीका-लातिनी अमेरिका के
तमाम गरीबों के बीच
जिस तरह पहुंचे वे यानों और
वाहनों पर सवार,
उसी तरह आये वे हमारे बीच।
भीख, दया, समर्पण और भय की
संस्कृति के प्रचारक
पुराने मिशनरियों से वे अलग थे,
जैसे कि उनके दाता भी भिन्न थे
अपने पूर्वजों से।
अलग थे वे उन सर्वोदयी याचकों से भी
जिनके गांधीवादी जांघिये में
पड़ा रहता था
(और आज भी पड़ा रहता है)
विदेशी अनुदान का नाड़ा।

●

भिखमंगे आये
अलग-अलग टोलियों में।
कुछ ने अपने पश्चिमी वैभवशाली दाताओं
की महिमा बखानी,
तो कुछ का दावा था कि वे
लुटेरों को उल्लू बनाकर
रकम ऐंठ लाये हैं
जनहित के लिए और
जनक्रान्ति की तैयारी के लिए
कुछ का कहना था कि
क्रान्ति की तैयारियों का भारी बोझ
न पड़े इस देश की गरीब जनता पर
इसलिए उन्होंने भीख से
संसाधन जुटाने का नायाब तरीका
अपनाया है।
कुछ का कहना था
कि क्रान्ति अभी बहुत दूर है
इसलिए वे तब तक कुछ सुधार ही
कर लेना चाहते हैं,
संवार देना चाहते हैं
दलितों-शोषितों-वंचितों का जीवन
एक हद तक
और फीस के तौर पर, बिना
नेता-नौकरशाह
बनने का पाप किये,
खुद भी जुटा लेना चाहते हैं
घर, गाड़ी वगैरह कुछ अदना-सी चीजें
और अगर खुद वे आ गये हैं
जनता की खातिर इस नर्क जैसे देश में
तो क्या इतना भी चाहना अनुचित है
कि उनके बेटे-बेटी शिक्षा पायें
अमरीका में?
कुछ का कहना था कि
अशिक्षा ही हमारे दुर्भाग्य का मूल है
अतः वे हमें शिक्षित करने आये हैं,
स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन के बारे में
बताने आये हैं।
कुछ का कहना था कि
हम सहकारी संस्था बनाकर
उत्पादन करें
तो हल हो जायेंगी हमारी
सारी दिक्कतें।
कुछ ने कहा कि
जो ट्रेड-यूनियनें न कर सकीं,
वे वह कर दिखायेंगे,
राज्यसत्ता तो चांद मांगना है,
वे हमें चवन्नी-अठन्नी के लिए
नये सिरे से लड़ना सिखायेंगे।
कुछ ने कहा कि दोष
कोर्ट-कचहरी-कानून और
सरकार का नहीं
हमारे गंवारपन का है
अतः वे हमें हमारे अधिकारों,
संविधान और श्रम-कानूनों के बारे में
पढ़ायेंगे
और जब हम जान जायेंगे कि
हमें सरकार से क्या मांगना है
तो हम मांगेंगे एक स्वर से
और हमारी याचना के तुमुलनाद
से जागकर, डरकर,
सरकार हमें दे देगी वह सब कुछ
जो हम चाहेंगे।

●

भिखमंगों ने हमें लताड़ा
कि यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियां
पूरी नहीं करती
तो हम उसका मुंह क्यों जोहते हैं?
यदि वह नौकरियां नहीं देती
तो हम खुद क्यों नहीं कर लेते
कुछ काम-धाम?
यदि वह सभी कारखानों को
पूंजीपतियों को दे रही है
और पूंजीपति हमें रोजगार नहीं दे रहे
तो हम स्वयं मिलकर क्यों नहीं
शुरू कर लेते कोई उद्यम
और फिर भी नहीं चलता काम
तो कम क्यों नहीं कर लेते
अपनी जरूरतें?
बन्द क्यों नहीं कर देते
ऊपर की ओर देखना?
चरम पर्यावरणवादी बन
चले क्यों नहीं जाते
प्रकृति की गोद में निवास करने?

●

भिखमंगों ने बेरोजगार युवाओं से
कहा–''तुम हमारे पास आओ,
हम तुम्हें जनता की सेवा करना सिखायेंगे,
वेतन कम देंगे
पर गुजारा-भत्ता से बेहतर होगा
और उसकी भरपाई के लिए
'जनता के आदमी' का
ओहदा दिलायेंगे,
स्थायी नौकरी न सही,
बिना किसी जोखिम के
क्रान्तिकारी बनायेंगे,
मजबूरी के त्याग का वाजिब
मोल दिलायेंगे।''
''रिटायर्ड, निराश, थके हुए क्रान्तिकारियो,
आओ, हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बतायेंगे।
वामपंथी विद्वानो, आओ
आओ सबआल्टर्न वालो,
आओ तमाम उत्तर मार्क्सवादियो,
उत्तर नारीवादियो वगैरह-वगैरह
आओ, अपने ज्ञान और अनुभव से
एन.जी.ओ. दर्शन के नये-नये शस्त्र और
शास्त्र रचो,''
आह्वान किया भिखमंगों ने
और जुट गये दाता-एजेंसियों के लिए
नई रिपोर्ट तैयार करने में।

●

भिखमंगों ने भीख को नई गरिमा दी,
भूमण्डलीकरण के दौर में
उसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दी।
भिखमंगों ने क्रान्ति और बदलाव की
नई परिभाषाएं रचीं।
भिखमंगों ने कहा–''भूल जाओ
'पैबन्द और कुर्ते का गीत' *
वह पुराना पड़ चुका है।
हम मांगकर लाते रहेंगे तुम्हारे लिए पैबन्द
तुम उन्हें सहेजना,
उन्हें जोड़कर एक दिन तैयार हो जायेगा
एक पूरा का पूरा कुर्ता।
भूख से तड़पते हुए मर जाओगे
यदि समूची रोटी चाहोगे।
हम तुम्हारे लिए मांगकर लाते रहेंगे
रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े,
तुम उन्हें खाते जाओ
एक दिन तुम्हारे पेट में होगी
एक साबुत रोटी।
मत करो बातें सारे कारखाने
और कोयला और खनिज और
मुल्क की हुकूमत पर कब्जे की,
ऐसी कोशिशें असफल हो चुकीं।''
हम पूछते हैं व्यग्र होकर,
''आखिर कब तक चलेगा
इस तरह''
वह तर्जनी उठाकर हमें रोकते हैं,
''हम एक अर्जी लिख रहे हैं।''
फिर वे एक रिपोर्ट लिखते हैं,
फिर चिन्तन करते हैं,
फिर दौरा करने किसी और दिशा में
चल देते हैं।
हम पाते हैं, भिखमंगे नहीं वे
अपहरणकर्ता हैं
बदलाव के विचारों के, स्वप्नों और
आशाओं के।
आत्मा की ऊष्मा के खिलाफ
सतत सक्रिय
शीत की लहर हैं ये भिखमंगे।

* 'पैबन्द और कुर्ते का गीत'–ब्रेष्ट की प्रसिद्ध कविता का सन्दर्भ

डब्ल्यू.एस.एफ. का महातमाशा...

डब्ल्यू.एस.एफ. को बेनकाब किया जाये। जो ईमानदार लेकिन दिग्भ्रमित प्रगतिशील बुद्धिजीवी डब्ल्यू.एस.एफ. में शामिल हैं उन्हें भी अगर इस छलावे से बाहर निकालना है तो यह जरूरी है कि बेलाग-लपेट ढंग से डब्ल्यू.एस.एफ. के असली चरित्र का पर्दाफाश किया जाये। इसके आयोजनों में भारी संख्या में लोग जुटते हैं इसलिए 'एकता-संघर्ष-एकता' का कोई रवैया अपनाया जा सकता है, यह सोचना घातक होगा और यह केवल भ्रमों को बढ़ाने का काम ही करेगा। डब्ल्यू.एस.एफ. के जमावड़े के समांतर क्रांतिकारी जनवादी शक्तियों तथा ईमानदार प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का कोई अच्छा जमावड़ा खड़ा कर लेना डब्ल्यू.एस.एफ. के बिछाये जाल में ही फंसना होगा। इससे एक झूठा आशावाद पनपेगा। जरूरत इस बात की है कि संघर्ष की दिशा को बेलाग-लपेट ढंग से स्पष्ट किया जाये, डब्ल्यू.एस.एफ. के खिलाफ खड़े हुआ जाये। कोई भी नरम या बीच-बचाव का रवैया अपनाकर 'डब्ल्यू.एस.एफ. में शामिल मित्रों' को वास्तविक संघर्षों के साथ नहीं खड़ा किया जा सकता। यह लोकरंजकतावाद होगा और इतिहास व सर्वहारा क्रांति के विज्ञान ने बार-बार यह साबित किया है कि जनता के सामने खड़ा किया गया उम्मीदों का कोई भी हवाई किला भरभराकर गिर पड़ता है और फिर हताशा-निराशा का एक नया दौर शुरू होता है।

मेहनतकश अवाम के पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्षों की चुनौतियों का ठोस ढंग से मुकाबला करके ही आज के ठहराव को तोड़ा जा सकता है।

किसी किस्म के लोकरंजकतावाद का सहारा लेना आत्मघाती होगा। इसलिए मजदूर वर्ग के सच्चे हरावलों को धारा के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होना चाहिए। ●

आर.एन.आई. पंजीयन संख्या - 71980è99, डाक पंजीयन संख्या - LW-NPè349e2003

गरीबी से बदहाल मां 10 रु. में बच्ची बेचने को मजबूर

और प्रधानमंत्री की बर्थडे पार्टी में पानी की तरह पैसा बहता है!

लखनऊ। "उड़ीसा में गरीबी से तंग आकर एक मां ने अपनी एक माह की बच्ची को मात्र दस रुपये में बेच दिया।" "झारखंड में एक रिक्शा चालक ने अपने बेटे को सौ रुपये में बेच दिया।" ... ये महज खबरें नहीं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढिंढोरा पीटने वालों के मुंह पर तमाचा है। कैसा लोकतंत्र? किसका लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र की यही तस्वीर होती है, तो ऐसे लोकतंत्र को जितनी जल्दी हो तबाह-बर्बाद कर दिया जाना चाहिए।

बच्चे भूख से मर रहे हैं, तंगहाली से परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सिर पर छत न होने के कारण ठंड से मर रहे हैं, कलेजे का टुकड़ा जिंदा रहे इसके लिए मां-बाप उसे बेच दे रहे हैं, यह है हमारा महान लोकतंत्र। यह हमारा महान लोकतंत्र है जहां जनता का प्रथम स्वयंसेवक प्रधानमंत्री अपने बर्थडे पर पैसा पानी की तरह बहाता है, जनता की गाढ़ी कमाई से पैसा निकालकर सरकारी लगुए-भगुए प्रधानमंत्री को "बर्थ डे" गिफ्ट देते हैं। हालात ये हैं कि सारे चुनावबाज नेता रोम के आतताई राजा नीरो की तरह सुख-चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा देश जल रहा है। नेता ही नहीं पूरा शासकवर्ग जनता के अथाह दुख के सागर में बने ऐयाशी के टापुओं में बैठा यह भूल चुका है कि यह सागर इसी तरह बढ़ता रहा तो उनके टापू भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। पूंजीपति वर्ग के टुकड़ों पर पल रहे सिद्धांतकार और कलमघसीट अंतकारी रोगों से घिरे पूंजीवाद के चिरंजीवी होने के लाख गीत रचें, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ पनप रही और बारूदी सुरंगों की तरह उनके "स्वर्ग" को घेर रही आम मेहनतकश की दिली नफरत का वे क्या करेंगे? अपने बच्चों को बेच देने की घटना बुर्जुआ मीडिया के लिए एक सनसनी भरी खबर हो सकती है, कुछ मतिमूढ़ मानवतावादियों के लिए रोने-कलपने का मसाला हो सकती है, लेकिन मेहनतकश जनता के बहादुर बेटे-बेटियों के लिये यह घटना एक चाबुक की तरह है, समय का चाबुक, जो कह रहा है खून के घूंट पीकर रणक्षेत्र में उतरने की तैयारी करो। सर्वहारा वर्ग की सेना में फिलहाली पस्तहिम्मती से खुशी में मगरूर पूंजीवाद कैसे रोकेगा इन रणबांकुरों को?

पूंजीपति वर्ग के स्वामिभक्त कुत्ते इन घटनाओं पर लाख लीपापोती करें, खबरों और असलियत से आम जनता को काटने के षड्यंत्र रचें, पर कामयाबी न उन्हें मिल सकी है और न मिल पायेगी।

उड़ीसा के अंगुल जिले के बदीबहल गांव में जब सुमित्रा बेहरा ने अपनी एक माह की बच्ची को दस रुपये में बेच दिया और यह बात अखबारों में आ गई तो उस जिले के उपजिलाधिकारी ने इस घटना पर प्रशासन की तरफ से लीपापोती की। उसने गरीबी के कारण बच्चे बेच देने के तर्क को खारिज करते हुए एक नायाब तर्क ढूंढ निकाला। उसने कहा यह मामला तो गोद लेने का है। यह है ऐसे मामलों में हमारे जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया। धन्य हो उपजिलाधिकारी महोदय, तुम्हारी स्वामिभक्ति से यह मानवद्रोही व्यवस्था धन्य हुई। ऐसी स्वामिभक्ति से तो जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता भी लजा जाये।

बुर्जुआ मीडिया ने भी इन खबरों को ऐसे पेश किया कि जैसे गरीबों में बच्चे खरीदना-बेचना जैसी घटनाएं अपवाद ही सही, होती ही रहती हैं। उन्होंने उन कारणों को तलाशने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों मां-बाप अपने दिल के टुकड़ों को बेचने के लिए मजबूर हैं। खैर, यह उम्मीद करना बेकार है कि मुनाफे के लिए निकलने वाले अखबार और टी.वी. चैनल इन कारणों पर जायेंगे। उनके लिए तो वाजपेयी का घुटना और धनाढ्यों की शराब पार्टियों जैसी खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपने को प्रगतिशील और जनवादी कहलाना पसंद करने वाले लेखकों-विचारकों की भी एक खास नस्ल है जिन्हें ये घटनायें नहीं दिखाई पड़ती हैं, उनकी आंखों में ऐसा मोतियाबिंद पड़ गया है कि उन्हें खास तरह की घटनाएं दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। आम जनता से कटे ये बुद्धिजीवी अक्सर उपदेशक की मुद्रा में नजर आते हैं। उपदेश देते हुए इनके गले की घुरघुराहट और सेठ के बंगले पर तैनात 'डोबरमैन' कुत्ते की गुर्राहट में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। फिर भी उपदेश दिये चले जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही राजकिशोर नाम के एक बुद्धिजीवी अपने एक लेख में मजदूरों को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, तो दूसरे लेख में अहिंसा के 'सोलिसिटर जनरल' की भूमिका में नजर आ रहे थे, ये वही हैं जो समय-समय पर विश्व सर्वहारा के महान नेताओं पर कीचड़ उछालने का काम करते रहते हैं। यह और बात है कि वह कीचड़ इन्हीं पर आ गिरता है। फिर भी अपने को कम प्रगतिशील नहीं समझते।

बहरहाल, भूख से तड़प कर मरते बच्चे, मौत से जूझते बच्चे बेचने को मजबूर मां-बाप और न जाने कितनी ही ऐसी ह्रदयविदारक घटनाएं हैं, जो इस पूंजीवादी व्यवस्था के गंदे, घिनौने चेहरे को उघाड़ कर सामने ला रही हैं। इसके साथ ही शासन-प्रशासन, न्यायपालिका और सत्ता के हर उस स्तंभ की असलियत को बेनकाब कर रही हैं, जो 'महान' लोकतंत्र के पहरेदार का बाना ओढ़े हैं और मेहनतकशों को अमानवीय और नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर देने के अपराधी हैं। मेहनतकशों के सामने सवाल इस बात का है कि अपराधियों को सजा देने के लिए वह कब तक किसी पीर-पैगंबर या किसी महापुरुष का इंतजार करेंगे? यह दुनिया इंसानों की मेहनत से ही बनी है और मेहनतकश ही इस दुनिया को बदलेंगे। इतिहास मेहनतकशों और खास तौर पर उनके बहादुर बेटे-बेटियों से वही सवाल कर रहा है जिसे कभी जर्मनी के क्रांतिकारी कवि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने ये शब्द दिये थे-

किस चीज का इंतजार है?
और कब तक?
दुनिया को तुम्हारी जरूरत है!

–मोहन

वर्ष 2003 : उदारीकरण के दौर का एक और काला वर्ष

जनता की लूट-बर्बादी, भ्रष्टाचार-दमन का एक और काला अध्याय

इसे उदारीकरण का तेरहवां वर्ष कहें या भाजपा नेतृत्ववाली राजग सरकार का छठवां वर्ष या सहस्त्राब्दी का तीसरा वर्ष, जो भी कहें, गुजरा वर्ष, 2003 आम जनता की तबाही-बर्बादी के एक और काले वर्ष के रूप में बीत गया।

गुजरात में सुनियोजित हत्याकाण्ड के सिरमौर, हिन्दुत्व की नयी नाक नरेन्द्र मोदी द्वारा मुसलमानों के खून से तिलक लगाकर फिर से राजगद्दी संभालने के बाद से गुजरे वर्ष का अन्त राजस्थान की नवनियुक्त भाजपाई राजरानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा पूरे राज्य के सरकारी विद्यालयों में 'वंदे मातरम' गाने की अनिवार्यता की घोषणा व प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर में अपने जन्मदिन को विलासितापूर्ण ढंग से बिताने के साथ हुआ। वर्षांत का यह ठीक वही समय था, जब चुनावी मदारियों की घृणित चालों से असम व बिहार में क्षेत्रीय उन्माद का घिनौना खेल चल रहा था, जनता मारी जा रही थी और महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा गैर मराठी लोगों के साथ उत्पात जारी था।

अठारह मुंह से अठारह बातें बोलने की कला के महारथी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भारतीय जनता पार्टी-विश्व हिन्दू परिषद का जहरीला नाग इस वर्ष और ज्यादा कुशलता के साथ एक तरफ अल्पसंख्यक विरोध से समाज को डंसता रहा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर उनका मंत्रिमंडल लगातार विदेश यात्रायें करता रहा और अमेरिकी-रूसी-जापानी आकाओं के तलवे चाटता रहा। सरकार, फलस्तीनी जनता का कत्लेआम करने, आजादी को हड़पने वाले इजरायली राष्ट्रपति एरियल शेरोन की भारत यात्रा पर पलक पांवड़े बिछाती रही और साइबर दुनिया के महाठग बिल गेट्स के स्वागत में गीत गाये जाते रहे।

गत वर्ष प्रधानमंत्री जब गणतंत्र दिवस की सलामी ले रहे थे तब उदारीकरण की नीतियां सफलतापूर्वक लागू करने के कारण उनकी छाती और ज्यादा फैली हुई थी और अपने सम्बोधन में उन्होंने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तेल कम्पनियों के विनिवेश (निजी हाथों में बेचने) की घोषणा की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके बेचने पर रोक लगाने से लेकर अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने तक की नाटक-नौटंकी होती रही। ब्याज दरों में कटौती का क्रम जारी रहा तथा कुछ और कम्पनियां बेच दी गयीं, ओ.एन.जी.सी. के दस प्रतिशत शेयर भी बेच दिये गये।

देशी-विदेशी पूंजीपतियों की ज्यादा सेवा करने की होड़ में कई राज्य सरकारें तो इस वर्ष केन्द्र से भी आगे निकल गईं। आंध्र प्रदेश के चन्द्र बाबू नायडू तो साइबर मुख्यमंत्री बन ही चुके थे, उत्तर प्रदेश के समाजवादी मुख्यमंत्री ने तो गद्दी संभालते ही प्रदेश के विकास का जिम्मा देश के शीर्ष पूंजीपतियों को सौंप दिया और राज्य की 24 चीनी मिलें लीज पर, निजी हाथों में सौंपने की घोषणा कर दी। उधर उत्तरांचल के विकास पुरुष मुख्यमंत्री एन डी तिवारी ने प्रदेश के उद्योगों को पूंजीपतियों की शीर्ष संस्था फिक्की को गोद दे दिया। पश्चिम बंगाल की लाल पताकाधारी वामपंथी सरकार तो इन सबको पछाड़ने में जी तोड़ से लगी रही। उधर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के आंदोलन को फासिस्टी तरीके से कुचलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया।

विगत वर्ष न्यायपालिका ने अपने मजदूर विरोधी तेवर को और ज्यादा उग्र करते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों से दो कदम आगे रहकर इस पूंजीवादी निजाम के प्रति और ज्यादा वफादारी निभाई। उच्चतम न्यायालय ने जहां एक तरफ तमिलनाडु सरकार द्वारा आन्दोलनरत राज्य कर्मचारियों के दमन को जायज ठहराया, वहीं उसने लम्बे संघर्षों के दौरान प्राप्त मजदूरों के जनवादी अधिकार को कुचलते हुए सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल को संवैधानिक, कानूनी यहां तक कि नैतिक नजरिये से भी गलत बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, साल के अन्तिम महीने में एक अन्य फैसले में इसने हड़तालियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकारों को एक निर्देश भी जारी कर दिया।

उच्चतम न्यायाल ने इस वर्ष अपने अन्य फैसलों में 'समान काम पर समान वेतन' के अधिकार को ही खारिज कर दिया, निलम्बन के बाद पुनर्बहाली पर देयकों के भुगतान के औचित्य को ही नकार दिया। उधर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक धरना-प्रदर्शन पर रोक का फरमान जारी कर दिया तो पटना उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका पर उंगली उठाने वाले की उंगली काट लेने की बात की। उत्तरांचल में नैनीताल उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अस्मिता तार-तार करने जैसी वीभत्स घटना के मुख्य अपराधियों में प्रमुख तत्कालीन जिलाधिकारी अनन्त कुमार सिंह को बरी कर दिया था। यह अलग बात है कि राज्य में व्यापक जनाक्रोश व जनांदोलन के कारण उच्च न्यायालय को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।

सन् 2003 में भी भ्रष्टाचार के कुछ और नये कीर्तिमान स्थापित हुए। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले में महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख धरे गये और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल भी इसमें फंस चुके हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता तांसी भूमि घोटाले में बरी हो गयीं। घूसखोरी में सी.बी.आई. का एक आला अफसर धरा गया, ताज गलियारे मामले में फंसी मायावती उत्तरप्रदेश की गद्दी खोने के बाद अपनी गर्दन बचाने के लिए जोड़-तोड़ में जुटी हुई हैं, महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य सचिव अखण्डप्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव लखू भाई पाठक मामले में उच्चतम न्यायालय से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गये। मधुमिता हत्याकाण्ड में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी फंसे पड़े हैं तो जेनी बलात्कार काण्ड में उत्तरांचल के हरक सिंह राव मंत्री पद से हाथ धो बैठे हैं।

भ्रष्टाचार की इस गटरगंगा में नहाने से भला न्यायपालिका कहां पीछे रहती। अब मजदूर विरोधी फैसले देकर वह सरकार से दो कदम आगे निकल चुकी है तो बाजारवाद और खुलेपन के इस युग में वह इस मामले में पीछे कहां रहती। बीते वर्ष भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश का एक न्यायाधीश वेश्यालय चलाने के मामले में धरा गया तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शमित मुखर्जी घोटाले में पकड़े गये। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक जज अमिताभ लाला सम्पत्ति बंधक रखने के दूसरे कोर्ट के एक मामले को छुट्टियों के दिन ही निपटाकर सुर्खियों में रहे। चण्डीगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस.एस. भारद्वाज सात लाख रुपये घूस लेते पकड़े गये। यह राशि जालंधर के हजाला व सत्र न्यायाधीश आर.एम. गुप्ता के जरिए हुए 11 लाख रुपये के सौदे का हिस्सा थी। यानी पूंजीवादी लूट के इस हम्माम में मंत्रियों से लेकर नौकरशाह, पुलिस, जज तक सबने अपने को और ज्यादा नंगा साबित किया।

दूसरी तरफ इन हालात से ऊबे परेशानहाल देश के मजदूरों-किसानों के संघर्ष भी कहीं तेज तो कहीं धीमे होते रहे, लेकिन किसी सशक्त क्रान्तिकारी राजनीतिक केन्द्र के अभाव में ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन इस वर्ष भी प्रायः दिशाहीन होकर बिखरते रहे। उधर ट्रेड यूनियन आंदोलन के महाधीश नेताओं की गद्दारियां इस वर्ष भी जारी रहीं। कांग्रेजी इंटक व संघी बी एम एस तो मजदूर आंदोलन के पीछे ढकलेने के लिए बनही ही हैं, लेकिन वामपंथी ट्रेड यूनियन महासंघों ने इस वर्ष भी मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किया।

मजदूरों के व्यापक दबाव में सीटू, एटक आदि ने इस वर्ष भी कदमताल के कुछ कार्यक्रम लिये। उन्होंने इन नीतियों के खिलाफ समा बांधने की कोशिश की और 26 फरवरी को संसद मार्च व 21 मई को एक दिनी देशव्यापी हड़ताल करके

(पेज 4 पर जारी)

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वानी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग: कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
सम्पादक: डा. दूधनाथ, मुकुल • सम्पादकीय पता: 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006 • सम्पादकीय उपकार्यालय: जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ